पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक
# समय माया

पंजीयन क्रमांक RNI-MP\HIN\2006/20685

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/march09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com
(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 4 अंक 48 | इंदौर, सोमवार 25 जनवरी से 31 जनवरी 2010 | पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 सत्ता दानवों की कल्पाएगी मानवों को

3 कल सबको मिले जल आज हो व्यवस्था

4 डकैत सुलेमान वसूली के लिए हर कदम रच रहा षड्यंत्र

5 सूचना के आवेदन में जानकारी न देने के षड्यंत्र

6 ऊपर से नीचे तक जालसाजियों का अम्बार

7 भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस, आईएफएस पर क्यों नहीं छापे?

### केंद्र की कांग्रेस का महंगाई से बड़ा षड्यंत्र

# खाद्य सुरक्षा के नाम बहुराष्ट्रीय कं. की कमाई सुरक्षा

केंद्र के कांग्रेसी गिरोह के डकैतों ने कमीशन खोरी के लिए जनता के मुंह से दाल, रोटी, गुड़, शक्कर, सब्जियां, तो महंगाई के कारण छीन ही ली हैं। फरवरी 09 की 15-16 रुपए किलो की शक्कर जनवरी 10 मेंही रुपए 45 प्रति किलो हो गई, चारों तरफ से जनता जो त्राहि-त्राहि कर रही है उससे बड़ा भी एक षड्यंत्र जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं स्तर अधि. 2006 बना दिया गया था पर इस चक्कर में कांग्रेस के विरुद्ध पूरे देश की जनता खड़ी हो जाने के डर से इस राक्षक को किताबी पिंजरे में कैद करके रखा गया था जो 1 अप्रैल 20 से लागू करने की पुरजोर तैयारी की जा रही है। इसके अंतर्गत समयमाया ने पूर्व में भी छापा जिसके चलते इस अधिनियम को कांग्रेस ने चुनाव तक के लिए टाल दिया था, अब जबकि गिरोह ने सत्ता पुनः षड्यंत्रों से हथिया ही ली है इस आजादी के बाद के सब बड़े जन विरोधी और बहुराष्ट्रीय कं. की न केवल सैकड़ों गुना कमाई वरन उनके कुकर्मों से किकसी की मौत भी हो जाए तो अधिकतम रुपए 5 लाख देकर हर अपराध से मुक्ति भी धारा 65 में व्यवस्था कर दी गई है। अर्थात बहुराष्ट्रीय कंपनी को हर

## 5 से 10 करोड़ सीधे बेरोजगार होंगे डकैतों को सीधा अरबों में कमीशन

अपराध करने गरीबों से निवाला तो क्या घूंटभर पानी भी बिना पैसे के न मिल सके और वह भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के विशाल दुकानों से जिसमें आम आदमी भी न घुस सके।

इसके अंतर्गत कोई भी किसान अपनी फसल को मंड़ी ले जाने तो दूर, खेत से भी नहीं उठा सकेगा ठेले, ताले, खोमचे वाले, चाय की गुमटी, पान वाले तक कोई व्यापार, दुकानदारी नहीं कर सकेंगे और करेंगे तो इनके न्यायालय जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. के नाम से जाने जाएंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी से सरकारी वेतन के अतिरिक्त उन्हें उनकी आवश्यकता से दुगुना दूध, दही, राशन, पानी पैकेज्ड आपूर्ति कर इन्हें अपने इशारों पर नचाते हुए इन सड़क छाप दुकानदारों पर रुपए 25000/- का न्यूनतम और अधिकतम रुपए 5 लाख तक का दंड करेंगे, जिससे अपने आप इस देश के 1 करोड़ से ज्यादा आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिना बहुराष्ट्रीय कं. के ब्रांड से बेचना तो दूर ढुलाई या लाना ले जाना भी नहीं कर सकेंगे। उसके परिवहन को भी न्यूनतम रुपए 25000 का दंड होगा।

शेष पेज 5 पर

### पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावना

# जिनपिंडों के मंडल में बादल-जीवन संभावित

विश्व के बड़े-बड़े वैज्ञानिक विशेषतौर पर नासा कभी मंगल पर जीवन की बात करता है, कभी चंद्रमा पर पानी होने के भारतीय दावे की पुष्टि करता है, तो धूर्त और जालसाज वहां प्लाट काटकर मूर्ख अमीरों को प्लाट बेच देते हैं।

जबकि इन सबके विपरीत भी ग्रह सौरमंडल के बाहर जीवन को धरती से भी दूरबीनों या रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित दूरबीनों से उन पिंडों पर जीवन होने या न होने के बारे में बहुत ही साधारण सी बात से भी पता लगाया जा सकता है कि यदि किसी सौर मंडल के ग्रह, पिंड, या हमारे सूर्य के तारा मंडलों ग्रह आदि के बाहर की आकाश गंगा में यदि सूर्य की तरह के अन्य ऊर्जा त्यागने वाले पिंड हैं तो उनके सौर मंडलों, ग्रहों, पिंडों पर अगर तरलता होगी तो जीवन होगा और तरलता न केवल हर जीवन का आधार होगी, वरन उस पिंड के वायुमंडल में उस सूर्य के ऊर्जा उत्सर्जन से बादल भी बनते होंगे और बादल बनते होंगे तो तरलता हमारी पृथ्वी के जल की तरह पिंड से बादल बनने और बरसने की सतत प्रक्रिया के विनिमय उस पिंड पर जीवन को गति देने में सक्षम होगा।

अब यदि मंगल पर जीवन की बात करें तो तरलता के बिना जीवन संभव नहीं और यदि मंगल पर जीवन होता तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में बादल होते और जब धरती से देखने पर यदि सीधी दृष्टि यदि मंगल पर पहुंचती है, तो वो सूखा है, वहां जीवन संभावित नहीं। नासा जो कि अमेरिकी संकर प्रजाति के धूर्तों की संस्था है बेशक उसकी कुछ

उपलब्धियां हैं उनका मूल काम है अमेरिकी साम्राज्यवाद को स्थापित करने के लिए दूसरे राष्ट्रों विशेषतौर भारत, चीन, रूस पर जासूसी करना अपना आतंक के माध्यम से डर बनाए रखने के लिए चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर पहुंच गए, नई आकाशगंगा खोज ली, सब धरती पर बैठे दूरबीनों से वहां के चित्र उतारना और उनको

शेष पेज 4 पर

### परमाणु बिजली पर अरबों का कमीशन डकारने के लिए

# देश की धरती को बंजर बनाने की साजिश

**अमेरिका समय बाधित परमाणु रिएक्टर लगाएगा भारत में**

भारत में भारतीय राष्ट्रीयकांग्रेस के नेता भले ही देश की मिट्टी की खरपतवार फसलें हों, जिन्हें दाना, पानी, खाद, सब देश से ही मिलता रहा है, परंतु काम ये केवल अपने आका ब्रिटेन और अमेरिका के लिए ही करते हैं, राष्ट्रगीत में उन्हें भाग्यविधाता कहकर जय कारे खुदने लगाए, वर्तमान पीढ़ी लगा रही है और धरती पर, भविष्य की पीढी जिसने हाल ही में कदम रखे हैं उनसे लगवाना शुरू कर दिए हैं।

स्वाभाविक है जब राष्टगीत में वंदना उन यूरोपियन आकाओं की जाएगी और गुलामी का गीत गाया जाएगा तो उनकी झूठन भी स्वयं चाटेंगे और देश की जनता को परोसेंगे, जैसा की हमारे महान भारत का पिछले दो-तीन हजार वर्षों की इतिहास रहा है, फिर अमेरिका, ब्रिटेन तो पिछले साठ वर्षों से अपना उपयोग के बाद

शेष पेज 7 पर

### प्रदेश के मुखिया का कार्यालय नंगे, भूखों और जालसाजों का अड्डा

# मुख्यमंत्री कार्यालय में पैसे नहीं लिफाफों के लिए

भोपाल। म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराजसिंग शक्ल से भले ही भोले बनकर छल रहे हो, पर मुख्यमंत्री कार्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा जालसाजों का अड्डा है। यह जनता और पूरा देश व दुनिया जानती है। जहां हर पल कोई न कोई षड्यंत्र की रचना चलती रहती है। जनता के भविष्य के नाम पर कैसे अरबों रुपए की हेरफेर की जाती है। गाहे बगाहे छन-छन कर बाहर आती रहती है। वहां प्रदेश की जनता का चुना हुआ मुखिया, सत्ता के शीर्ष में बैठकर अपने दरबारियों के साथ पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, माफियाओं, सफेदपोश अपराधियों के साथ मिलकर शतरंगी बिसात पर बैठकर शासन तंत्र के मोहरों अपने फायदे के लिए ही हर काम करते हैं।

**पत्र बिना लिफाफे के भेजे जाते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय से**

चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने लिखा है-"सत्ता सदा से ही षड्यंत्रकारियों का केंद्र रही है। यह तथ्य धर्मशास्त्रों, नीतिशास्त्रों, राजनीति, सबका सहस्त्रों वर्ष पुराना या यूं कहें कि जब से मानव सभ्यता का सामाजिकरण हुआ तब से ही सर्वमान्य कटु सत्य है।"

शेष पेज 2 पर

### यूरोपियन राष्ट्र अपने कुकर्मों के दुष्परिणामों को थोंप रहे गरीब राष्ट्रों पर

# वैश्विक ऊष्णता, कोपेनहेगन रहा असफल

विश्व में अमेरिका और सभी यूरोपियन राष्ट्र न केवल अपने उद्योगों, वरन् वाहनों में पेट्रोल और डीजल के उपयोग से अन्य विश्व की अपेक्षा 70% ज्यादा वायुमंडल को प्रदूषित करते हुए कार्बन डाई आक्साइड, कार्बनमोनो आक्साइड, ग्रीन हाऊस गैसेस के साथ ही उद्योगों से भी अन्य कई विषैली गैसों को उत्सर्जित करते हैं।

जिससे पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य किरणों की तीक्ष्णता को कम करने वाली संघनित आक्सीजन जिसे ओजोन कहा जाता है धीरे-धीरे विलीन होती जा रही है, जिसके दुष्परिणामों से पृथ्वी पर सूर्य की तीक्ष्ण किरणें सीधे प्रहार करती है, इसके फलस्वरूप पृथ्वी के निकट का वायुमंडल गर्म होने से ध्रुवों की बर्फ पिघलने से लेकर हिमालय के ग्लेशियरों की लुप्तता

शेष पेज 2 पर

**यूरोप कुकर्मों से भयभीत वातावरण की उष्णता का असर आएंगे तूफान दर्द की एकमात्र दवा है सघन वृक्षारोपण**

## सम्पादकीय

# सत्ता दानवों की-कल्याणी मानवों को

भारत के धार्मिक पुराणों, शास्त्रों में कंस, धृतराष्ट्र जैसे शासकों, राक्षसों का चरित्र वर्णित है, वो इतिहास की कल्पित कल्पनाएं भी माने जाएं तो भी दानवों, कंस, धृतराष्ट्रों की वर्तमान संदर्भ में भी संज्ञाएं नाम और चरित्र से से ही विद्यमान हैं। बस नाम और युग बदला है। परंतु इतिहास पुनरावृत्ति हो रहा है। कैसे राष्ट्र में पर्याप्त ऊपजों और खाद्यान्नों का भंडार है, परंतु जनता को दो वक्त की रोटी भी दुर्लभ हो रही है। सत्ता में बैठे दानवों में मनमोहनसिंह, मंत्री शरद पंवार, वाणिज्य मंत्री कमलनाथ, राष्ट्रवासियों के मुंह से निवाला छीन विदेशों को मात्र कमीशन खोरी के लिए बेच, छीन रहे हैं। पिछली फरवरी -09 में जो शक्कर 15 रुपए किलो थी वही इस जनवरी 10 में 45 रुपए किलो हो जाएगी। उ.प्र. में किसानों को गन्ने का लागत और मेहनत का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि शक्कर 300% महंगी हो गई, वही हाल महाराष्ट्र में भी है। वहां भी गन्ना उत्पादक आंदोलनरत हैं। पर सत्ता के दानवों को राष्ट्र के मानव की ये कल्पन और पीड़ा नहीं दिख रही, उन्हें बस दिख रहा है केवल धन कैसे और कहां से नोंचा जाए।

मानव सत्ता पाते ही मानव बन जाता है यदि वह सत्ता स्वीकारने वाले मानवों के हित चिंतन, विकास और समृद्धि का मार्ग अपने अधीनस्थ मानवों के लिए प्रशस्त करता है, जब वही सत्ता प्राप्त महामानव अपनी ही जनता को कष्ट, पीड़ा, मानसिक शारीरिक संत्रास बांट कर स्वयं सारे सुखों को भोगता है तो दानवों की श्रेणी में आ जाता है। जो अन्य अधीनस्थ मानवों के हितों पर कुठाराघात पर उन्हें दो वक्त का भोजन भी न मिलने दे उनकी मेहनत के फलों को भी छीन कर लालन-पालन में बाधा बनने लगे। कांग्रेसी दानवों का इतिहास रहा है कि वो मुंह से और मीडिया में अनुदानों जो शासन का ही पैसा जो जनता से करों के रूप में वसूला जाता है के दानवीर बनते हैं पर वास्तविक चरित्र में दानवों की परिपाटी निभाते हैं। जालसाजी, छलकपट, लूट का इतिहास दोहराते हैं। मानवों के रुलाते हैं, भूखा, सुलाते हैं। जनहित चिल्लाते हैं और सुनाते हैं वास्तविकता में जनहित स्वयं डकार जाते हैं। फिर भी मानवीय आदरणीय, सम्माननीय सोनियाजी, मनमोहनजी, शरद पंवार जी, कमलनाथ, के नारे लगवाते हैं। जबकि ये धूर्त, दानव जिन मानवों के वोटों से जीत कर आते हैं उन्हीं के हितों को कदम-कदम निगल जाते हैं। फिर भी जन के धन से राजमार्गों पर अपनी प्रशंसा के होर्डिंग्स लगवाते हैं। कदम-कदम पर दानवों को मुस्कारेत देख, मानव कलप जाते हैं। अपनें खून, पसीने की कमाई को बर्बाद देख हृदय से आंसू बहाते हैं। दानव अपनी वाहवाही करवानें, आतंकी हमले करवाते हैं। दंगे भड़काते हैं। दहशत फैलाते हैं। बाजारों में महंगाई लाते हैं। गरीबों को रुलाते हैं। जनता व मीडिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाते हैं। चिल्लाते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, गरीब को 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। धीरे से फुस्कारते हैं, कमीशन के लिए फिर दोहराते हैं विदेशों से आयात करेंगे (सड़ा हुआ माल) गरीबों को भूखा नहीं सोने देंगे। बेरोजगारों को बांटते हैं वोट के लिए भत्ता, दानवों की ऐसी ही होती है सत्ता।

## वैश्विक ऊष्णता...

पेज एक का शेष

तक सामने आ रही है। वातावरण और पर्यावरण को बिगाड़ने वाले अमेरिका और यूरोपीय देशों जहां पर 4 से 6 माह तक बर्फ जमी रहती है, सबसे ज्यादा खतरा उत्पन्न होने लगा है। अपने इन पर्यावरण को बिगाड़ने वाले जो पूरे विश्व के अन्य राष्ट्रों के मुकाबले मात्रर 15% जनसंख्या होने के बाद भी स्वयं के साथ 85% पूरे विश्व के पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए न केवल जिम्मेदार है वरन वैश्विक उष्णता के पृथ्वी की हजारों वनस्पतियों और अन्य हजारों जल, थल और नभचरों को नष्ट करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। ये धूर्त मक्कार संकर प्रजाति के राक्षसों को अब ये डर सताने लगा है कि यदि अब ये नहीं चेते तो प्राकृतिक आपदाओं, जिसमें भारी बर्फबारी, तूफान, सबसे ज्यादा इन्हीं को नष्ट करेंगे और नष्ट कर रहे हैं।

दूसरी ओर ये स्वयं सारे दक्षिण और उत्तरी अमेरिकी देशों साथ पूरे यूरोप जो अपने कुकर्मों को देखना तो नहीं चाहते परंतु एशियाई, अफ्रीकी देशों को अपने उत्सर्जन में कटौती करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं ये स्वयं यूरोपिय नहीं झेल रहे हैं, इन्हें डर यह सता रहा है कि इन गरीब अर्द्धविकसित, विकासशील देशों ने भी यदि उनकी ही तरह ग्रीनहाऊस गैसेज, विषैली कार्बन मोनोक्साइड गैसों का उनके वाहनों से औद्योगीकरण से यदि उत्सर्जन शुरू कर दिया तो यूरोपिय देशों में पूरे वर्षभर न केवल आपदाएं कहर ढाएंगी वरन उनके भी समुद्र किनारे बसे देशों का डूबने का सिलसिला निकट भविष्य में ही शुरू हो जाएगा। इसलिए हर हाल में अमेरिका राष्ट्रपति ओबामा-चीन जियाओ बांग, भारतीय मनमोहन और दक्षिण अफ्रीकी नेताओं के साथ मिलबकर किसी निष्कर्ष और उष्णता को कम करने के लिए डेनमार्क के कोपहेगन में प्रयास करते रहे। अकेले अमेरिका में कुछ प्रदेशों में 15इंच बर्फ दिसम्बर के तीसरे-चौथे सप्ताह में ही गिर गई, अमेरिकी राज्यों के समुद्र तटों पर गाहे बगाहे तूफान आते ही रहते हैं, अर्थात प्राकृतिक आपदाओं की भीषण त्रासदियां ज्यादा वातावरण बिगाड़ने वाले ही झेल रहे हैं।स्वाभाविक सी बात है कि डर और दहशत भी उन्हीं में ज्यादा है। इसके विपरीत स्वयं अपने उत्सर्जन पेट्रोल और डीजल की खपत, औद्योगिक प्रदूषण के साथ ही अमेरिका ही पूरी दुनिया में स्वयं परमाणु बमों के परीक्षण, जल और थल में करता है। जब जलमें करता है तो जो तूफान, भूकंप बाढ़, अतिवृष्टि आते हैं तो संकर शैतानों की ये फौज उसे सुनामी का नाम देकर बच लेती है और कहर एशियाई राष्ट्र झेलते हैं। दूसरी ओर थल पर हिन्दुकुश घाटी में भी उसने अक्टूबर 8,05 से लगातार 2 नवम्बर 05 तक लगातार और 2-3 चार दिनों के अंतर से भूमिगत बम विस्फोट कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, चीन और भारत को भूकंपों से आतंकित किया और खुले में शक्ति प्रदर्शन कर वास्तविकता मेंतो पूरे वातावरण में उष्णता ही बढ़ाई और पर्यावरण नष्ट किया, इन कुकर्मों पर अमेरिकी, नाटो और यूरोपीय शैतान लगाम नहीं लगाना चाहते उल्टे ही वैश्विक उष्णता के नाम पर विकासशील देशों यथाचीन और भारत पर दबाव बनाकर दोहरी चाल चलते हैं। पहले तो ये कि इस बहाने उनके यहां विकसित होते औद्योगीकरण को रोका जाए, साथ ही बढ़ते स्वचलित वाहनों यथा कार,, ट्रकों, बसों, मोटर सायकलों में पेट्रोल, डीजल के उपयोग को प्रतिबंधित कर अपने लिए पर्याप्त स्टाक बचाने का षड्यंत्र भी रच रहा है। ताकि सभी यूरोपीय राष्ट्रों को उनकी जनता और सैन्य उपयोगल के लिए पर्याप्त पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता अधिकतम समय तक बनी रहे, अन्यथा जिस तेजी से एशियाई राष्ट्रों में विशेषतौर पर चीन और भारत में वाहनों की संख्या के साथ पेट्रोल डीजल का उपभोग बढ़ रहा है इस शताब्दी के अंत तक समाप्त हो जाने की आशंका भी इन यूरोपियन और अमेरिकी शैतानों को कहीं न कहीं तो सता रही है। वैश्विक उष्णता के नियंत्रण के बहाने वो उत्सर्न केनाम पर औद्योगिकरण और पेट्रोल के उपभोग पर प्रतिबंध भी लगा सकें। जबकि पूरी दुनिया के कुल उपभोग का 50% अमेरिकी शैतान और 20 से 25% अन्य यूरोपीय राष्ट्र करते हैं।

डेनमार्क के कोपेहेगन में 192 राष्ट्रों के जो प्रतिनिधियों को एकत्रित करने का जो नाटक किया गया उसमें अमेरिकी और यूरोपियन शैतानों ने सारे प्रतिबंध एशियाई और तीसरी दुनिया के अफ्रीकी राष्ट्रों पर लगाने के लिए दबाव बनाया, इसके विपरीत स्वयं उन उपद्रवियों ने अपने ही कुकर्मों उत्सर्जनों से भयभीत है। कोई प्रतिबंध स्वीकार नहीं, यहां तक कि पूर्व की क्योटो संधि को भी नहीं माना।

संकर अमेरिकीयों श्वेतांग यूरोपियन व विश्व के 192 राष्ट्रों के शैतानों ने केवल सिक्के के एक पहलू को देखा दूसरे पहलू पर न तो ध्यान दिया न विचार-विमर्श, दर्द है तो दवा है और दवा है तो बीमारी भी खत्म की जा सके, परंतु दर्द हल्का ही किया ही जा सकता है। इस समस्या के निदान हेतु वर्तमान में

1. जंगलों को विकसित किया जाए, नए वनों के लिए शीघ्र व्यवस्था की जाए।
2. क्रांकीट के शहरी जंगलों में सघन वृक्षारोपण किया जाए।
3. प्रण लें कि एक व्यक्ति कम से कम दो पेड़ लगाए और संरक्षण करें।
4. हर चार पहिया छोटे वाहन के नए उत्पादन या बिक्री के साथ दो पेड़ लगाने संरक्षित करने, दो पहिया के लिए 1 पेड़ विकसित और संरक्षित किया जाए।
5. भारतीय रोड कांग्रेस के उस सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाए, जिसमें सड़क की चौड़ाई के बराबर दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण किया जाए, ताकि वाहनों से निकलने वाला सारा धुंआ दोनों तरफ से निकलने वाले कार्बन डाटईआक्साइड व मोनाआक्साइड पेड़ सोखकर शुद्ध आक्सीजन उत्सर्जित कर सके और न केवल पर्यावरण प्रदूषण रोका जा सके वरन् सड़कों की उम्र बढ़ाने के साथ यात्रा करने वालों का सफर सुहाना और ताजगीभरा हो।
6. बढ़ते शहरीकरण और कांक्रीट जंगलों के बीच हरियाली और सघन वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से कानूनन बाध्य किया जाए।
7. वनों को संघनीकृत करने की अनिवार्य व्यवस्था हो, जिसके लिए सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था हो।
8. कृषि भूमि पर 10% मात्र में सघन वृक्षारोपण, फलदार पौधों की अनिवार्यता हो।
9. जल, जंगलों, जानवरों के संरक्षण, स्कूली पाठ्यक्रमों में व्यवस्था की जाए, उचित परिणाम आने में 20-25 वर्ष लगेंगे, परंतु ये सभी तत्काल लाभप्रद होंगे।
10. औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में उपयोग की गई भूमि से दुगुनी भूमि पर उद्योगों के चारों तरफ सघन वृक्षारोपण किया जाए। ताकि ग्रीन हाऊस गैसेस को वृक्ष आसानी से शोषित कर सकें, यदि उपरोक्त सुझावों पर ही अक्षरशः पालन कर लिया जाए तो भी वैश्विक उष्णता को रोका जा सकता है।

## मुख्यमंत्री कार्यालय...

पेज एक का शेष

जनता के नाम जनता के काम के नाम, आम आदमी के हितों का हर पल सौदा सत्ता ही बेरहम काम होता है। जनता के सामने जनता के दुख में शरीक होकर उनके साथ आंसू बहाने से न चूकने वाले पीछे क्या-क्या षड्यंत्र रचते रहते हैं उसका 1% भी जनता के सामने या मीडिया में नहीं आता, जो सामने आता है वो सच से मीलों दूर होता है। जिस मुखिया के कार्यालय में बैठे धूर्तों और मक्कारों की फौज कितनी निकम्मी, भ्रष्ट और बत्तमीज है इसका अंदाज मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायत के जवाब में पत्र क्र. 8344/ एल.एम.एस./ पी.यू.बी./2009 भोपाल दिनांक 12.10.09 को हस्ताक्षरित पत्र वहां से नवम्बर के अंत में प्रेषित किया गया जो इंदौर में 1.12.09 को मिला। जिस पर न तो लिफाफा था, उसी पत्र पर स्टांप मीशन से स्टपिंग कर मोड़ कर भेज दिया गया। बेशक पत्र गोपनीय स्तर का था, चलिए इसे भी त्याग दिया जाए, अगर यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री कार्यालय भारी मितव्ययिता कर लिफाफे के 20 पैसे भी बचत करना चाहता है। बहुत प्रसन्नता की बात है, यदि ईमानदारी से यही मितव्ययिता पूरे प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में अपनाई जाए तो स्वाभाविक है शासन का प्रतिमाह करोड़-दो करोड़ खर्च बचेगा। इसके विपरीत सत्ता में बैठे चाहे मुख्यमंत्री, सचिवों, अधिकारियों अन्य मंत्रिय, संत्रियों के रग-रग में भ्रष्टाचार और वसूली के लिए जालसाजियां रची-बसी हों, उनकी मितव्ययिता मरम्मत के कोट पर पोलिथीन का पैबंद नजर आती है। जहां जनता की आंख का आंसू जब तक नहीं बहने दिया जाता जब तक उससे वसूली का स्त्रोत नहीं दिखता, जैसे ही आंसू का स्त्रोत वसूली स्त्रोत बनता है तो फिर आंसू पोंछने के लिए रूमाल नहीं कंबल और त्रिपाल लेकर दौड़ पड़ते हैं, ताकि आंसू वहीं बहता रहे और आंसू बहाने वाले को तब तक ढांक दिया जाए, जब तक उस स्त्रोत से अगली वसूली और आय का स्त्रोत



CM Monit-C

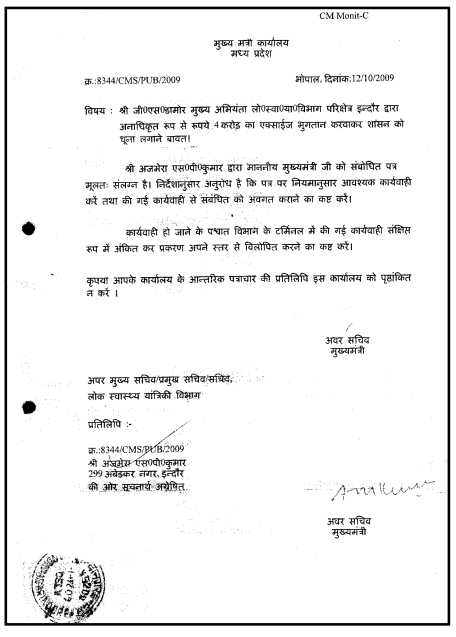

मुख्य मंत्री कार्यालय
मध्य प्रदेश

क्र.:8344/CMS/PUB/2009 — भोपाल, दिनांक:12/10/2009

विषय : श्री जी0एस0डामोर मुख्य अभियंता लो0स्वा0या0विभाग परिक्षेत्र इन्दौर द्वारा अनाधिकृत रूप से रूपये 4 करोड़ का एक्साईज भुगतान करवाकर शांसन को चूना लगाने बावत!

श्री अजमेरा एस0पी0कुमार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र मूलतः संलग्न है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा की गई कार्यवाही से संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें।

कार्यवाही हो जाने के पश्चात विभाग के टर्मिनल में की गई कार्यवाही संक्षिप्त रूप में अंकित कर प्रकरण अपने स्तर से विलोपित करने का कष्ट करें।

कृपया आपके कार्यालय के आन्तरिक पत्राचार की प्रतिलिपि इस कार्यालय को पृष्ठांकित न करें।

अवर सचिव
मुख्यमंत्री

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

प्रतिलिपि :-

क्र.:8344/CMS/PUB/2009
श्री अजमेरा एस0पी0कुमार
299 अंबेडकर नगर, इन्दौर
की ओर सूचनार्थ अग्रेषित

अवर सचिव
मुख्यमंत्री

नजर न आने लगे।

इस बारे में दो महत्वपूर्ण उदाहरण जो ताजे हैं 3000 के ज्यादा सहकारी गृहनिर्माण संस्थाएं पूरे प्रदेश में 50वर्षों से सदस्यों को लूट कर संचालक करोड़पति, अरबपति बन रहे थे। उसमें जिला कलेक्टर, नगरनिगमसे लेकर मुख्यसचिवों, मुख्यमंत्रियों तक खुली वसूली और लूटपाट चल रही थी। सदस्य शिकायत करते थे हराहो जाती थी। जैसे ही बड़ी बहुराष्ट्रीय कालोनाइजर कं. ने हर वर्ष दो अरब रुपए मुख्यमंत्रीकार्यालय में फैंकने शुरू किए पहले वर्ष में उन्होने छोटीमोटी नजूल की सरकारी ग्राम पंचायतों की जमीनों पर अवैध कब्जे किए और उन्हें अड़चन न आए बड़ी-बड़ी कालोनियां देश के सभी बड़े शहरों में काटकर बड़े-बड़े अवैध क्रांकीट जंगल बिना उचित कानूनों के पालन का पालन किए खड़े कर दिया। 3-4 वर्षों में वो जब खड़े हो गए तो उन्हें बेचने के लिए ग्राहक चाहिए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को फिर अरबों रुपए देकर ग्रहनिर्माण संस्थाओं पर शिकंजा कसने, जनता को सच्चाईयां बताने ऐसी संस्थाओं पर कार्यवाही करने व करवाने के लिए दबाव बनाया। 50वर्षों से उन गृहनिर्माण संस्थाओं के सदस्यों के आंसू नहीं पोछे गए जैसे ही बड़ी वसूली हो गई तो पुलिस, प्रशासन सब सक्रिय हो उठे, उनके आंसू पोंछने के लिए कानून का कंकाल और त्रिपाल लेकर दौड़ पड़े, जो लुट,पिट चुके थे उन्हें ढांकने की कोशिश की जा रही है।

सड़कों के मामले में सत्ता केषड्यंत्रकारियतों को समझ में आ गया कि सड़कें जनता की समृद्धि और विकास के लिए प्राथमिक आवश्यकता है, तो उन्होंने लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाते हुए सभी महत्वपूर्ण राज्य व राष्ट्रीय राजमार्गों पर बीओटी लगाकर ठेकेदारों को लूटने और वसूली के लिए अधिकृत कर अधिकांश सड़कें 25से 30वर्ष के लिए बेच दी। हर सड़क में जो बीओटी पर दी गई 25% अग्रिम में इन तीन धूर्तों स.वि.नि. प्रबंध संचालक सुलेमान, मुख्य सचिव राकेश साहनी और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने डकारा और हर वर्ष लूट और वसूली जो टोल टेक्स के नाम पर वसूली जाएगी 10 से 25% उसमें भी वसूली की जा रही है और वसूली जाएगी, इनके लिए सारे नियम-कानून बलाए ताक रख दिए, यहां तक कि अधिकांश बीओटी ठेकेदारों ने सड़क निर्माण में लगाई गई गिट्टी, पत्थर, मुरम, रेती तक की रायल्टी का पूरा भुगतान म.प्र. खनिज विभाग तक को नहीं किया गया, आखिर शीर्ष सत्ता ही डकार रही हो तो फिर ठेकेदार से काहे की नियम-कानूनों के पालन की अपेक्षा की जा सकती है? मुख्यमंत्री कार्यालय में भले ही लिफाफे के पैसे न भी हो पर अरबों रुपए के ऐसे षड्यंत्रों को तोहर पल अंजाम दिया जाता है ये उदाहरण तो खोपड़ी के बाल भी नहीं।

## शादी नहीं सौदेबाजी...

पेज 8 का शेष

चाहिए जिसे अब वो जब चाहे जहां चाहे इच्छानुसार गले में पट्टा डालकर डोरी अपने हाथ रखकर अपनी सुरक्षा और समाज में समारोहों में अपनी अच्छानुसार प्रस्तुत कर सकें, अब चूंकि स्वयं स्त्रीयां आत्मनिर्भर हो गई हैं और कमाने लगी हैं तो जब मन में आए उसे खिलाएं, पिलाएं उपयोग करें अन्यथा पाले हुए श्वान की भांति घर के दरवाजे से बांध कर रखें, ताकि उनकी सामाजिक सुरक्षा बनी रहे।

अब जहां तक पुरुषों का सवाल है जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी जैसा उच्च वैश्य वर्ग अपनी समाज की लड़कियों के चौंचलों और सौदेबाजी के चलते खुले में ढेर ग्रामीण आदिवासी और हरिजन लड़कियों से शादी दहेज देकर करने में भी न केवल आगे है, वरन् गृहस्थी बसाने के लिए लाखों रुपए भी खर्च करके दक्षिण भारत, महाराष्ट्र के महिला प्रधान क्षेत्रों से भी शादी करके ला रहे हैं।

जबकि इस समाजों में ही लड़कियों की कमाई के कारण उनके ही मां-बापों और रिश्तेदारों ने उन लड़कियों को 45-50 की उम्र भी पार करा दी, पर समाज के तथाकथित स्वयंभूओं ने भी उन्हें न तो आगाह किया और न ही सामाजिक दबाव बनाकर उनके माता-पिता को शादी के लिए दबाव डाला। वैसे भी जैनियों की संख्या जो सन 2000 में 1 करोड़ से ज्यादा थी। घट कर 2011 में 75 से 80 लाख ही रह जाएगी जैन समाज में 35 से 40 की उम्र के 30% लड़के कुंवारे हैं। पर इस समाज की दुकानदारी के कर्णधार स्वयंभू में इसे लेकर कोई चिंता नहीं है। जबकि 60% लड़कियां उच्च शिक्षित होने, कमाऊ होने, विधार व तलाकशुदा होने, धनाभाव या उनके परिवार के स्वार्थी होने या परिवार को जिम्मेदारी संभालने वाला कोई न होने के कारण अकेली निःसंदेह यह हाल लगभग सभी उच्चवर्गीय और शिक्षित में स्पष्ट दृष्टिगोचर है। पर समाजों के स्वयं-भू कर्णधारों को अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए वो समाज के मंच का उपयोग करते हैं। उन्हें समाज के पतन समुचित विकास और समाज के अन्य परिवारों की वास्तविक परेशानियों से कोई मतलब नहीं, कर्णधारों को स्वार्थ पूर्ति के लिए चंदा, भीड़ और मंच मिले उनकी आवश्यकता तक ही सीमित है। ताकी ये कर्णधार अपना चंदा चला सकें।

ये सब कारण बन रहे हैं कुंवारे बढ़ती पुरुषों की संख्या, स्त्रीयों की संख्या, कुंठाएं, बिखरते परिवार।

### जहां हाथ डालो, लूटपाट और भ्रष्टाचार से लबालब

# नगर निगम, पालिकाएं विशुद्ध डकैतों के अड्डे

## शिक्षा, खाद्य निरीक्षण, स्वास्थ्य, राशनकार्ड, बाजार, पेंशन सरकारी योजनाएं सबके रखरखाव, निर्माण कर व वसूली सबमें वर्षों से बैठे अजगर सब कुछ निगलने में लगे हों

**हर विभाग बिजली, पानी, सड़क, भवन अनुज्ञा, साफ सफाई सम्पत्तिकर व अन्य कर**

**इंदौर।**

नगर निगम, परिषदों और पालिकाओं में चाहे वो बड़े शहर की, छोटे शहर की या कस्बों की जहां भी निगाह जाती है, लूटपाट का तांडव और भ्रष्टाचार से लबालब भरे पाए जाते हैं। अधिकारी और पार्षद केवल कमाने आते हैं।

पूरे प्रदेश में बिजली की बचत के नाम, वैपर लैंपस, हाई पावव मर्करी बदल कर कानों कान खबर भी नहीं हुई और बदल गए, पहले उनको लगाने में करोड़ों रुपए जनता के धन से बर्बाद किए गए, जमकर क्रय करने में कमीशन खाया गया, रुपए का माल 4 रुपए से लेकर 10 रुपए तक में खरीदा गया, जैसे इंदौर, उज्जैन, नगरनिगम में रुपए 20 हजार का प्लास्टिक के पेड़ जो वर्ष भर में ही बंद हो गए, कहीं रुपए 80 हजार में तो कहीं रुपए 1,20 हजार में खरीदे गए, जबकि वास्तविकता में माल रुपए 10 हजार का भी नहीं था। पर हाय-रे कमीशन तेरी बलिहारी, यहां तो गोबर के लड्डू भी किसी सोने के भाव

खरीदते हैं। हरामखोर श्वानों क़ी फौज बस कमीशन भर मिलता रहे अकेले इंदौर में ही सारे शहर में बिजली बचत के नाम पर लगाई गई पतली ट्यूब लाइटों की खरीदी गई रुपए 10 करोड़ से ज्यादा की ट्यूब लाइटों में रुपए 5 करोड़ का कमीशन था। उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा में भी कमीशन करोड़ों में ही डकारा गया, केवल ट्यूब लाइटों, उनके फिक्सचर्स, फिटिंग और बदलवाने में, बाकी रखरखाव के नाम पर औसतन रुपए 1 लाख का खर्च आ रहा है, बेशक कमीशन महापौर, निगमायुक्त, इंजीनियर, प्रभारी, पार्षद से लेकर वहां का चपरासी तक डकार रहा है।

कालोनी सेल, सफाई निर्माण, शिक्षा, बाजार, विभाग, बगीचा और पर्यावरण जल वितरण, चिड़िया घर, सड़कें, सम्पत्ति आवारा पशु, स्वास्थ्य सम्पत्तियों के रखरखाव, राजस्व, रिमूवन गैंग आदि सभी में चारों तरफ भ्रष्टाचार का तांडव मचा रहता है। निगमायुक्त से लेकर जल वितरण व निकासी के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, का.अ. सहा. यंत्री, उपयंत्री, वही निर्माण, सड़कों को भी संभालते हैं। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खाद्य की गुणवत्ता साफ-सफाई आदि भी देखते हैं। पर निगमों में होने वाले कानूनों की धज्जियां उड़ाने वाला तांडव और गैर कानूनी कार्यों को को करने वाला तांडव भी देखने योग्य होता है, स्वास्थ्य विभाग का डाक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी, तकनीकी निर्माण से लेकर तोड़फोड़ आदि भी देखते हैं। पर निगमों में होने वाले कानून की धज्जियां उड़ाने वाला तांडव और गैर कानूनी कार्यों को करने वाला तांडव भी देखने योग्य होता है। स्वास्थ्य विभाग का डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी, तकनीकी निर्माण से लेकर तोड़फोड़ का प्रभारी बना दिया जाता है। डॉ. पुराणिक जैसे लोक रिमूवल गैंग के प्रभारी बन जाते हैं और गेडफंड को बचाने और कानूनी दांवपेंच फंसाकर धन कमाने में लग जाते हैं। पार्षद जैसे ग गोबर का जानने वाले अंगूठा टेक स्वास्थ्य समिति के प्रभारी बनाए जाएंगे, फिर क्षेत्रीय होने के कारण अपनी दोस्ती और दोस्ती निभाएंगे। चंदा दाता के गुण गाएंगे। नकली मावा, घी, दूध, मसाले, खाद्य तेल नकली पकड़े जाएंगे तो इन्हें जनता के भविष्य से नहीं वर्तमानसे मतलब है, कमाएंगे और बचाएंगे।

सफाई के नाम से दोस्तों के यहां का कचरा उठाएंगे और चंदा न देने वाले दुश्मनों के यहां फिकवाएंगे। जब वो चिल्लाएगा तो बोलेंगे निगम का काम है वो तो ऐसे ही होता है। सफाई करवाना है तोपैसे लगेंगे, जल वितरण और उसका राजस्वसे आय तो जनता वर्षों से भुगत ही रही है, पानी मिले न मिले बिल तो मध्यमवर्गीय, नौकरीपेशा को तो देनाही पड़ेगा, उनका भी जो मुफ्त के पानी से फैक्ट्रीयां और दुकानदारी चला रहे हैं। गाड़ियां, घर और कुत्ते नहला रहे हैं। नेतागिरी, अफसर गिरी कर रहे हैं। नेताओं को चंदा बांट रहे हैं, सफेद खद्दर धारियों को पाल रहे हैं, उनका भी वो बिल दें न दें चंदा तो देते हैं। पूरे प्रदेश में निगमों, पालिकाओं से लेकर ग्राम पंचायतों में जल राजस्व के नाम पर मात्र 40% जल राजस्व वसूल होता है।

वैसे भी राज्य सरकारों को पानी और बिजली जैसी उपभोक्ताओं की सेवाओं से कमाई के लिए न केवल अफसर वरन नेता मंत्री से लेकर पार्षदों की लार टपकती रहती है। राज्य सरकारें इन सेवाओं से सीधे कमाई के लिए इन सेवाओं को निजी हाथों में देकर दोनों हाथों, लूटने के लिए भारी बेताब दिखती है। इसलिए राज्य सरकारें पहले पूरे प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कंपनियों, फिर नगरीय निकायों की व्यवस्था बहुराष्ट्रीय और बड़ी कंपनियों को सौंप कर जनता से भारी भरकम कीमतें वसूलेंगी, शहरीय निकायों में चलने वाली यहां तक की कचरा उठाने की व्यवस्था भी निजी कंपनियों को सौंपने का भी प्रयोग कर चुकी है, परंतु हर बार असफलता ही हाथ लगी है।

नगरीय निकायों में चुने हुए प्रतिनिधियों से लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों सबकी निगाहें हर काम में लूटने खाने की रहती है। वहां फाइलें, रजिस्टर गुमने की घटनाएं बहुत सामान्य सी बातें हैं। चाहे वो कालोनियों की हो, बहुमंजिला भवनों,जानवरों के चिड़िया घरों, सफाई व्यवस्था में कर्मियों की भर्ती हो, स्वास्थ्य में प्रकरण लगाने सबमें लेनदेन कीजिए सब जालसाजों की मर्जी से हो जाएगा। आम जनता का ख्याल यहां केवल वोटों के दृष्टिकोण से ही रखा जाता है। निगम कानून किताबों में लिखी होते हैं किताबों के लिए होते हैं। पालन करवाना उनकी मर्जी औ धन के वजन पर निर्भर होता है। इंदौर को ही लें तो सूक्ष्म व्यवस्था तो दूर वृहत व्याख्या किस्से कहानियां यहां से निकलने वाले अनेकों दैनिकों में रोज ही भरे पड़े रहते हैं।अब प्रदेश की अधिकांश नगरीय निकायों में जो अभी नए चुने हुए पार्षद और महापौर निर्वाचित हुए हैं। जनता की सुख सुविधा और आदर्श की बातें चुनाव के पहले नारों और वादों के लिए थी। चुनकर पद संभालने के बाद अब ये खद्दरधारी सफेद डकैत उन्हीं कामों में हाथ लगाएंगे, जिनमें इन्हें कमाई और वसूली दिखेगी, फिर कमाई वसूली के तरीके भी बहुत सारे हैं, नियमों के विपरीत बिना टेंडर अपने लोगों में कई गुना ज्यादा कीमत पर माल खरीदना, काम करना शर्तों में दर्शित स्तर के विफरीत घटिया स्तर का माल खरीदना, काम करवाना, जैसा कि सड़कों भवन निर्माण से लेकर विद्युत सामग्री, साफ-सफाई सामग्री से लेकर कचरा ढोने के ट्रकों, पाईप लाईनों, सीवन लाइनों जैसे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट में पूरे देश-प्रदेश, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर व प्रदेश के 150 से ज्यादा नगरी निकायों में हुआ हो रहा है, होगा, सफेदपोश डकैत निर्वाचित या नियुक्त बटोरने के लिए होते हैं।

### म.प्र. खाद्य एवं औषधि प्रशासन जनहित से नहीं सरोकार पैसे फेंकों,तमाशा देखो

# भ्रष्ट निरीक्षकों को महीना दो सब कुछ मिलावटी बेचो

**भोपाल।**

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मुख्यालय में बैठे नियंत्रण जिसे खाद्य एवं औषधि का क,ख,ग नहीं आता, दूसरा राज्य प्रशासनिक का अधिकारी राकेश श्रीवास्तव ने इँडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर पदोन्नतियां प्राप्त की है। स्वाभाविक है वो श्वान धन नोंचने के लिए यहां बैठा है, उसे तो म.प्र. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधि. 1954 और ड्रग्स एंड कास्टमेटिक एक्ट 1940 की अ.आ.इ.ई. भी नहीं जानता उसे तो वहां बैठे चार उपनियंत्रक औषधि के और वरिष्ठ खाद्य निरीक्षक यह बता देते हैं कि यहां हस्ताक्षर की चिड़िया बैठाने के इतने लाख मिलेंगे ये बंदा बस आंख मींचकर हस्ताक्षर कर नोट अंटी कर लेता है।

स्वाभाविक है पूरे प्रदेश के खाद्य एवं औषधी निरीक्षक कैसा तांडव कर रहे होंगे अंदाज लगाया जा सकता है। खाद्य एवं औषधि के पूरे प्रेदश के सारे निरीक्षक बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीयों जो आषधिया और खाद्य वस्तुओं का प्रसंस्करण कर या सीधे ही पेक करती हैं। इन श्वानों को हर महीने टुकड़ा डालकर धड़ल्ले से औषधियों खाद्य पदार्थों से मिलावट कर पूरे प्रदेश की जनता को परोस रही है, इसलिए सभी बड़ी औषधि निर्माता से महीना खाने के साथही अगर उनके नमूने स्तरहीन पाए भी जाते हैं तो उन्हें मोटे-मोटे स्तरहीन दंड देकर बचा लिया जाता है और छोटी-छोटी फैक्ट्री मालिकों को जो इनकी मांग पूरी नहीं कर पाते हैं उन्हें प्रकरण लादकर वाहवाही लूटी जाती है और सरकार व जनता के सामने लक्ष्य और उपलब्धियां दिखाई जाती है।

वर्तमान में म.प्र. खाद्य एवं नियंत्रक विभाग नगर पालिका और पंचायतों की तरह काम कर रहा है, जब नियंत्रक ही अनपढ़ सरपंच और महापौर की तरह काम कर रहा है भाड़ में जाए जनता और उसके हित खाद्य एवं औषधि के सभी निरीक्षकों से महीना वसूली कर उन्हें खुली छूट पूरी लूट की इनकी बला से जनता कुछ भी खाए-पिए नियंत्रक को इससे कोई सरोकार नहीं,ये तो आंख मींच कर धन कहां से आएगा, आ रहा है को जपने के लिए यहां बैठा है। बेशक स्वास्थ्य मंत्री अनूप मिश्रा को देकर ही यहां बैठा है, तो मात्र वसूली के लिए जैसे भूतपूर्व नियंत्रक सलोनी सिंग करती थी, वही हाल इसका है। जबकि बड़ी-बड़ी कंपनियां जिसमें रेन बैक्सी, प्लेथिको, ल्यूपिन इफ्का आदि जो अपने आप को अंतरराष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय की श्रेणी में रखती है रुपए 5 के खाद्य लायसेंस जो नगर निगम से ही बन जाते हैं पर नट्रस्विंट टाइट के डिब्बे बाजार में सैकड़ों गुना ज्यादा कीमत पर बेच कमारही है ये आँखें मीचें बैठे तक रहे हैं।

सभी दैनिक समाचारपत्रों में स्तन कड़े करने, लिंग लंबा करने, लंबाई, मोटाई बढ़ाई, वजन कम करने जैसे अश्लील और भ्रामक विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। न केवल नियंत्रक, वरन पूरी म.प्र. सरकार केवल वसूली में लगे रहकर ऊंघ रही है। जबकि जनता की युवा पीढ़ी इन भ्रामक विज्ञापनों से भ्रमित होकर हर रोज करोड़ों रुपए दांव पर लगा रही है और बर्बाद हो रही है, पर न तो ये ड्रग्स एंड कास्टमेटिक एका. 1940 में कार्यवाही कर पा रहे हैं न ही नोटों की हरियाली के सूरदासों को मेडिकल कोड एंड ईथिक्स ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवरटीजमेंट एक्ट 1956 के अंतर्गत कोई कार्यवाही करने में न जो जिलाधीश न ही कोई न्यायालय, कोई कार्यवाही कर रहे हैं, जबकि सारे न्यायाधीश उच्च न्यायालयों के साथही सत्र व जिला न्यायालयों के वर्षों से ऐसी बकवास अखबारों में हर रोज देख रहे हैं।

भोपाल के मुख्यालय से लेकर सभी जिलों के उपसंचालक स्तर पर बैठे निरीक्षक, सारे के सारे केवल वेतनके बदले कागजी खानापूर्ति कर चारोंत रफ मात्र वसूली में लगे हैं। इस विभाग से सूचना के अधिकार में प्राप्त दस्तावेज बताते हैं कि इस विभाग की खाद्य प्रयोगशाला में हर महीने औसतन 2500 खाद्य के नमूने भेजे जातेहैं जिसमें से 95% नमूने मिलावटी होते हैं। बेशक इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पूरे प्रदेश में बैठे अधिकांश खाद्य निरीक्षक जो लगभग 256 हैं। हर माह रुपए 2 से 3 लाख वसूली कर अधिकांश बहुराष्ट्रीय कं., बड़ी कंपनियों, मिलावटियों, पेकर्स, प्रसंस्करण करने वालों से वसूला जाता है। छोटे उत्पादकों, विक्रेताओं से नमूने लेने के नाम पर चमका-धमका, भयभीत कर वसूली की जाती है और नमूने असली माल के लेकर प्रयोगशाला में भेजे जातेहैं। यदि यहां सौदा नहीं पट पाता तो रुपए 10 से 25 हजार लेकरस्वयं प्रयोगशाला का लोक विश्लेषक आर.पी. मिश्रा पैसे लेकर जांच रिपोर्ट ही बदल देता है। म.प्र. खाद्य प्रयोगशाला के इस लोक विश्लेषक के पास वर्तमान मेंही रुपए 50 करोड़ से ज्यादा की नामी-बेनामी सम्पत्ति है।

म.प्र. के सभी 50 जिलों में बैठे खाद्य निरीक्षकों जो न केवल महाभ्रष्ट वरन् महाजालसाज भी हैं, इस नियंत्रक राकेश श्रीवास्तव को महीना या तिमाही, छह माही, वार्षिक किस्त लाखों में इन जालसाजों से मिल जाती है तब ही वो 3-3 वर्ष से ज्यादा होने पर भी ये निरीक्षक एक ही स्थान पर डंटे रहते हैं। इंदौर में सचिन लोंगरिया, उज्जैन में खा.नि. अरविन्द पथरोल, देवास में बैठी खा. नि. सुषमा पथरोल को व प्रदेश ऐसे ही अनेकों निरीक्षकों को बैठे वर्षों गुजर गए पर इन हरामखोरों के स्थानांतरण नहीं हुए।

भोपाल में बैठा नियंत्रक और उसकी पूरा स्टाफ कितने हरामखोरों और जालसाजों का अड्डा है यह सारे तथ्य सूचना के अधिकार में दिए गए पत्रों, अपीलों के जवाब से मिलता है। दूसरा नियंत्रक कितना नियंत्रण कर पा रहा है, विभागीय गतिविधियों और जनहितों पर कितना ध्यान दे पा रहा है, इसका अँदाजा इसी बात से लगता है कि इसके नवम्बर 09 में आदेश के बाद भी इंदौर उज्जैन संभागों के सभी जिलों को उपसंचालकों खाद्य एवं औषधि ने तीन माह बाद भी अभी तक सारी जानकारी नहीं भेजी। जब ये सारे खाद्य एवं औषधि निरीक्षक अपने नियंत्रक के आदेश को नहीं सुनते-मानते तो जनता के स्वास्थ्य से जुड़े इस विभाग में कैसा भ्रष्टाचार और जालसाजियां हर कदम की जा रही होंगी अंदाजा लगाया जा सकता है।

### रु. ४000 से ५000 में नए घरेलू कनेक्शन

## सरकारी घोषणा रु. 1000 की बाकी सब लूट

**इंदौर।** सभी भारत सरकार की तेल कंपनियां अर्थात भारत पेट्रोलियम हिन्दुस्तान और इंडियन आईल तीनों ही, ओएनजीसी और गैस अथारिटी ऑफ इंडिया की गैस पाईप लाईन बिछते देख जनता से माल बटौरने में और सही अर्थों में ठगने में जुट गई है। इसलिए अधिक से अधिक गैस कनेक्शन देकर जनता को फांसना चाहती है। जैसे ही गैस पाईप लाईन से गैस मिलना शुरू होगी ग्राहक अपने-अपने गैस कनेक्शन वापस कर जमा राशि मांगने दौड़ेंगे इसलिए उस कमाई को स्थाई बनाए रखने, कमीशन डकारने और व्यवसाय चलाने और बचाने के लिए धड़ल्ले से गैस कनेक्शन देने की मात्र रुपए 1000/- में घोषणा तो कर दी गई, परंतु डीलर तो इस स्वर्णिम अवसर को भुनाने की ताक में ही रहता है। इंदौर के इन तीनों कंपनियों के डीलर रुपए 4200/- से रुपए 5000/- वसूल कर जबरदस्ती रुपए 2500/- का चूल्हा भी टिका रहे हैं। रुपए 50 का गैस रेल्यूलेटर रुपए 200 में बेच रहे हैं। इन सबके विपरीत रसीद रुपए 1650/- मात्र की ही दी जा रही है। इस संबंध मेंखाद्य नियंत्रक या नागरिक आपूर्ति का वसूली नियंत्रक धूर्त परमार जो 5 वर्ष से बैठा है और उसके वसूलीकर्ता धूर्त दरबारी मीना सेंगर व अन्य सभी ये वही मीना है जिसे इंदौर में कुंडली मारे बैठे 20 वर्ष से ज्यादा हो गए। जब ज्यादा हल्ला मचता है तो साल छह महीने अपने कुकर्मो से भड़की आग को शांत करने यहां वहां चला जाता है और फिर लौट कर इंदौर में। से पूछताछ की गई तो वही इस जालसाज परमार का रटा रटाया जवाब नहीं कहीं से कोई शिकायत नहीं है, आप शिकायत करेंगे तो हम जांच (मोटी वसूली) करेंगे और फिर बताएंगे। सरकारी घोषणावीर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री घोषणाएं तो बढ़ी-बढ़ी करते हैं। बेशक घोषणाओं से पहले वसूली और जनता को लूटने के षड्यंत्रों की कूट रचना पहले कर ली जाती है। चाहे वो गैस कनेक्शन से लेकर नल कनेक्शन है। सरकार घोषणावीर घोषणाएं ही इसीलिए करते हैं, ताकि जनहितों की आड़ में स्वहित ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक लेनदेन की प्रक्रिया में सबको अपना-अपना हिस्सा तरीके से मिलता रहे। 48घंटे में गैस मिल जाएगी, कम से कम म.प्र. के 350 से ज्यादा डीलर और तेल कंपनियों ने तो नहीं दे रही क्या कर लिया केंद्र और राज्यों के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने फिर गैस कनेक्शन और सिलेण्डर ही क्यों? क्या पेट्रोल पम्पों पर साधारण पेट्रोल 60 आक्टेन का और प्रीमियम 80 आक्टेन का मिल रहा है। नहीं कल 35 रुपए लीटर के पेट्रोल 25 रुपए लीटर के डीजल में भी मिलावट हो रही थी और अब रुपए 50 लीटर के पेट्रोल और रुपए 33 लीटर के डीजल में भी मिलावट हो खाद्य विभाग के मंत्री, जिलों के नियंत्रक और निरीक्षक कल भी महीना वसूल रहे थे और आज भी वसूल रहे हैं। कल भी पेट्रोल डीजल मिट्टी तेल मिलाया जा रहा था और आज भी मिलाया जा रहा है। प्रदेश और देश के हर जिले की यही कहानी है। जब तक जांच के ऊपर नियंत्रण और नियंत्रण पर भी जांच की दोहरी गलाकाट प्रतियोगिता नहीं होगी और एक दूसरे के विपरीत कार्य शैली की प्रणाली लागू नहीं की जाएगी सब लूट पाट करेंगे।

## लोक निर्माण विभाग प्रधान सचिव के भ्रष्टाचार का तांडव

# डकैत सुलेमान वसूली के लिए हर कदम रच रहा षड्यंत्र

## नियमों, कानूनों की, वसूली के लिए, उड़ा रहे धज्जियां, कर रहे तांडव

**भोपाल।**

म.प्र. लोक निर्माण विभाग के जोनल और मंडल कार्यालयों को बंद करने, वहां बैठे प्रमुख अभियंताओं, मंडल अभियंताओं को अधिकार विहीन बनाने के लिए खैरात में बैठाए गए विद्युत यांत्रिकीय के प्रमुख अभियंताओं शैलेन्द्र शुक्ला के साथ मिलकर प्रधान सचिव, म.प्र. सड़क विकास निगम में आठवर्ष से अजगर की तरह लिपटा बैठा मो. सुलेमान हर कदम षडयंत्र रच कर अरबों रुपए प्रतिवर्ष की वसूली कर रहा है, सारी प्रदेश की अच्छे यातायात वाली सड़कों को बीओटी ठेकेदारों को 25 से 30वर्ष के लिए सौंपकर चाहे सड़क सिंगल लेन 15 फुट की हो क्यों न हो दोनों हाथ वाहन चालकों व मालिकों से लूट व वसूली का तांडव कर रहा है, जिसे मात्र समयमाया पिछले 7वर्षों से लगातार प्रकाशित कर रहा है, जबकि अधिकांश बीओटी सड़कों पर वसूली करके 6-7 वर्ष गुजरने के बाद भी दोनों ओर पट्टियां नहीं भरी गई है सड़कें न केवल खराब वरन असुरक्षित होने के बाद भी बीओटी ठेकेदार में दरें बढ़ाकर अवश्य वसूली कर रहे हैं, इसके विपरीत सड़क निर्माण विभाग में बैठे संभागीय कार्यालयों में लोक निर्माण विभाग के महाभ्रष्ट इंजीनियरों को चुन-चुन कर बैठाया ही इस शूकर सुलेमान ने बैठाया ही इसलिए है कि उसके लूट और वसूली में कोई परेशानी न आए, जहां तक मुख्यमंत्री शिवराजसिंग और मुख्य सचिव राकेश साहनी का साला है, जबकि इन्हें सैकड़ों शिकायतें हर रोज सड़कोंसे संबंधित पूरे म.प्र. की जनता कर्मचारियों, अधिकारियों से मिल रही है। परंतु ये अर्थ चिंतन में लीन हो केवल नोटों की माला जपने में लगे हैं। इन्हें मालूमहै इनकी औकात कि कितने दिन सत्ता में रहना है, बस अर्थ चिंतन करो जनता लुटे या मरे वह लुटने और मरने के लिए पैदा हुई है।

समयमाया की सत्यता और कड़वी नीम की औषधि का असर जनता पर हो न हो परंतु लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियोंको सत्यता जब समझ में आ रही है जब उनकी नौकरियां और अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा है। तब इन दोनों खैरातीलाल प्रमुख अभियंता शैलेंद्र शुक्ला और सफेद पोश डकैत इंडियन एव्यूसिंगसर्विस अधिकारी मो. सुलेमान के षड्यंत्रोंकीशिकायत मुख्यमंत्री जो स्वयं सत्ता के तालाब में बैठकर बगुलों की तरह धन रूपी 24घंटे अर्थ चिंतन में लगा रहता है, कैसे सुनेगा कर्मचारियों और अधिकारियों की पुकार, फिर भी मुख्यमंत्री को की गई शिकायत की प्रति यहां संलग्न है-

महोदय,

उपरोक्त विषय मेंनिवेदन है कि लोक निर्माण विभाग में विगत कुछ दिनों से उच्चशीर्ष पर पदस्थ पदाधिकारियों द्वारा मातहत परिक्षेत्रीय/ मंडल कार्यालयों को समाप्त किए जाने की मुहिम छेड़ी गई थी, लेकिन इस प्रयास का खुलासा हो जाने से पुरजोर विरोध होने के कारण इस मुहिम को रोक दिया गया एवं उच्च शीर्षपर पदस्थ पदाधिकारियों को मुंह की खाना पड़ी।

इससे शीर्ष पद पर पदस्थ पदाधिकारियों ने अपने इस प्रयास को नए रूप में अमलीजामा पहनाने के लिए अधिनस्थ कार्यालयों के कार्यों को शासन के नियमों की अवहेलना करते हुए अवैधानिक रूप से अपने हाथ में लेकर इन कार्यालयों को बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसके उदाहरण निम्नानुसार हैं-

1. निविदा आमंत्रण के लिए म.प्र. शासन, लोक, निर्माण विभाग भोपाल द्वारा उनके पत्र क्र. डी/योजना/61/19 भोपाल, दिनांक16.5.2001 द्वारा कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री/ मुख्य अभियंताओं अधिकार दिए हैं, शासन द्वारा इस संबंध में प्रमुख अभियंता को किसी प्रकार के अधिकार नहीं सौंपे गए हैं, लेकिन प्रमुख अभियंता द्वारा अपने पत्र क्र. 401/सा/1045/सी.एस.एस./3694 दिनांक 26.10.2009 से मुख्य अभियंता (सीएसएस) का गठन कर सी.आर.एफ. योजना के तहत विभिन्न कार्यों को रुपए 490.00 करोड़ की निविदाएं प्रमुख अभियंता कार्यालय में आमंत्रित की गई जो नियमों के विरुद्ध है जबकि इसके लिए परिक्षेत्रीय कार्यालय/ मंडल कार्यालय एवं संभागीय कार्यालय में पदस्थ अधिकारी सक्षम हैं।

2.तकनीकी स्वीकृति के लिए म.प्र. शासन वि.वि. मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. 879/2008/नियम/चार/395 दिनांक 23.5.2008 से कार्यपालन यंत्री को रुपए 20.00 लाख अधीक्षण यंत्री को रुपए 3.00 करोड़ तक तथा मुख्य अभियंताओं को सम्पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। प्रमुख अभियंता को तकनीकी स्वीकृति के कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। शासन द्वारा दिनांक 18.12.2009 के माध्यम से 24 मुख्य जिला मार्गों के कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। जिसके लिए भी प्रमुख अभियंता कार्यालय को तकनीकी स्वीकृति के किसी प्रकार के अधिकार न होने पर भी प्रमुख अभियंता ने अपने पत्र क्रमांक 236/मुख्य जिला मार्ग/ 09/4062/दिनांक 29.12.2009 द्वारा एक प्रकोष्ठ गठित किया जाकर नियम विरुद्ध तकनीकी स्वीकृति आदि दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

3. म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग भोपाल मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र. एफ. 15-7/19/बजट/90 भोपाल दिनांक 15.5.2000 द्वारा आवश्यक सामग्री क्रय की अनुमति हेतु मुख्य अभियंता को अधिकृत किया गया है, लेकिन प्रमुख अभियंता द्वारा अपने आर्थिकहितों के संधारण के लिए शासन की अवहेलना करते हुए उनके पत्र क्र. 404/सा/050/क्रय/3311 दिनांक 30.9.2009 द्वारा मार्ग से संबंधित आवश्यक सामग्रीयों के क्रय के लिए उनके कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रकार इस कार्य का भी अतिक्रमण किया है। इनकी यह कार्यवाही अधिनस्थ कार्यालयों के अधिकारों में शासन की अनुमति बगैर किया गया सीधा-सीधा अतिक्रमण है।इसकी जांच भी का जाए।

4. म.प्र. शासन वित्त विभाग द्वारा परिक्षेत्रीय/मंडल कार्यालयों में पदस्थ मुख्य अभियंता/ अधीक्षण यंत्री को अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उपयोग मंडल/परिक्षेत्र में पदस्थ अधिकारी ही कर सकते हैं। कार्यालय में संलग्न किसी भी अधिकारी (कार्यपालन यंत्री से मुख्य अभियंता तक) को पृथक से कोई वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित नहीं किए गए हैं, क्योंकि यदि कार्यालय में संलग्न अधिकारियों को इस तरह के अधिकार प्रदान किए जाते तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती, क्योंकि संलग्न अधिकारी मेदानी पदस्थ अधिकारियों के अधिकारों का उपयोग कर समानांतर कार्य करने लगते। वित्त विभाग से अधिकार प्राप्त किए बगैर /शासन की बगैर अनुमति के प्रमुख अभियंता कार्यालय में संलग्न मुख्य अभियंताओं को जो मुख्य रूप से मुख्य अभियंता भी नहीं है, बल्कि अधीक्षण यंत्री है. के द्वारा निविदा आमंत्रण एवं तकनीकी स्वीकृति दी जा रही है। जो नियम विरुद्ध होकर जांच का विषय है।

निविदा आमंत्रण/ तकनीकी स्वीकृति के अधिकार वित्त विभाग द्वारा क्रमशः परिक्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता एवं मंडल कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री को प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारियों से यह कार्य न लिया जाकर प्रमुख अभियंता कार्यालय में संलग्न अधिकारियों से यह कार्य बगैर अधिकार के सम्पादित कराकर समानांतर कार्यालय चलाए जाने का नियम विरुद्ध प्रयास किया जा रहा है। परोक्ष रूप से इन कार्यालयों के कार्यों का नियम विरुद्ध अतिक्रमण कर इन कार्यालयों को बंद करने की दिशा में उठाया जा रहा कुत्सित कदम है। जो एक गंभीर अनियमितता के साथ अधिकारियों द्वारा स्वयं के आर्थिक हितों के संधारण में किया जा रहा कार्य है जो गहन जांच का विषय है।

अतः हम समस्त स्थानीय ठेकेदार/ कर्मचारी/अधिकारी जनहित में आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस केंद्रीकरण की नीति के तहत लोक निर्माण विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों के अधिकारों का किए जा रहे केंद्रीकरण को तत्काल समाप्त किया जावे तथा जिन अधिकारियों द्वारा अधिकार के बिना किए जाना आर्थिक हितों में किए जा रहे अनियमित कार्यों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को दण्डित करने की कृपा करें।

निवेदक

समस्त कर्मचारी/अधिकारी/ठेकेदार, लोक निर्माण विभाग

प्रतिलिपिः-

1. वित्त मंत्री, म.प्र. शासन भोपाल की और प्रेषित कर निवेदन है कि आपकी स्वीकृति एवं अधिकारों के बगैर प्रमुख अभियंता कार्यालय में निविदा आमंत्रण एवं तकनीकी स्वीकृति के अधिकार न होने पर भी उनके द्वारा किए जा रहे नियम विरुद्ध ऐसे कार्यों की जांच कराई जावे।

2. लोक निर्माण मंत्री म.प्र. शासन भोपाल की और निवेदन है कि वित्त विभाग एवं आपकी स्वीकृति के बगैर प्रमुख अभियंता कार्यालय में आमंत्रण एवं तकनीकी स्वीकृतिके अधिकार न होने पर भी उनके द्वारा किए जा रहे नियम विरुद्ध ऐसे कार्योंकी जांच कराई जावे।

3. श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष भोपाल

4. श्री अजय सिंह माननीय विधायक भोपाल

और प्रेषित कर निवेदन है कि लोक निर्माण विभाग में प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर किए जा रहे निविदा आमंत्रण एवं तकनीकी स्वीकृति आदि के कार्य नियम विरुद्ध है इस प्रकार के कार्य के अधिकार इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है। इस विषय पर अपने स्तर पर विधानसभा आदि में विरोध प्रदर्शन करने की कृपा करें।

5. अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग, भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर कर्मचारियों/ अधिकारियों का हनन किया जा रहा है। इस विषय पर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

6. रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर की ओर प्रेषित करे निवेदन है कि जनहित के इस मुद्दे को संज्ञान लेकर अपने स्तर से शीघ्र कार्यवाही करने की कृपा करें।

7. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी भोपाल/ ग्वालियर की ओर भेजकर निवेदन है कि आपके द्वारा लोक निर्माण विभागों प्रमुख अभियंता में पदस्थ वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं के संभागीय कार्यालयों में पदस्थ लेखाधिकारियों द्वारा भी उक्त नियम विरुद्ध कार्यवाही को शासन एवं आपके ध्यान में नहीं लाया जा रहा है। इससे इकी कार्य प्रणाली भी संदिग्ध प्रतीत होती है। कृपया इस नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

8. प्रमुख सचिव, वित्त म.प्र. शासन भोपाल की और भेजकर निवेदन है कि प्रकरण की जांच कराई जाने का कष्ट करें।

9. लोकायुक्त कार्यालय भोपाल की और प्रेषित कर निवेदन है कि जनहित के इस मुद्दे पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा आर्थिक लाभ संधारण हेतु किए जा रहे अनियमित कार्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

10. आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो भोपाल की और प्रेषितकर निवेदन है कि जनहित के इस मुद्दे पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा आर्थिक लाभ संधारण हेतु किए जा रहे अनियमित कार्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

11. प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि जनहित के इस मुद्दे पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा आर्थिक लाभ संधारण हेतु किए जा रहे अनियमित कार्य की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

12. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल की ओर भेजकर निवेदन है कि आपके द्वारा की जा रही नियम विरुद्ध कार्यवाही कर तत्काल रोक लगाई जावे।

13. समस्त मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग अपने अधिकारों पर अवैध रूप से किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

14. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग अपने अधिकारों पर अवैध रूप से किए जा रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

15. अध्यक्ष, लेखाधिकारी संघ भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि संभागों में पदस्थ लेखाधिकारियों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

16. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघ भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि अधिनस्थ कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

17. अध्यक्ष तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि अधिनस्थ कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

18. अध्यक्ष लिपीक कर्मचारी संघ भोपाल की और प्रेषित कर निवेदन है कि अधिनस्थ कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के अधिकारों के हनन को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

19. अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी कांग्रेस, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि अधिनस्थ कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों के अधिकारोंके हनन को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

20. अध्यक्ष ठेकेदार एसोशिएशन भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि स्थानीय ठेकेदारों को कार्य से वंचित किए जाने हेतु प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा आमंत्रित निविदाओं के विरोध में कठोर कदम उठाने का कष्ट करें।

निवेदक

समस्त कर्मचारी/अधिकारी/ठेकेदार

लोक निर्माण विभाग

## जिनपिंडों ...

पेज एक का शेष

विस्तृत कर उन पर यान उतारना दिखा देना और विश्व के पढ़े-लिखे मूर्खों पर अपनी दहशत के साथ सर्वोच्चता स्थापित करना, ये कार्य अमेरिका पिछले 60वर्षों से ज्यादा समय से न केवल कर रहा है, वरन अपने कुकर्मों और करतूतों में सफल भी रहा है, जबकि पढ़े-लिखे मूर्खों के पास सामान्य ज्ञान को खर्च करने की भी क्षमता खो जाती है। क्योंकि सामान्य ज्ञान के लिए भी दिमाग की नसों पर जोर देना पड़ता है, जबकि अंतरिक्ष में जब सब शून्य है तो आपके सारे यानों की शक्ति भी शून्य हो जाएगी। ईंधन को जलाने के लिए आक्सीजन चाहिए और तरल आक्सीजन भी कितने हजार टन ढो सकने वाले वाहनों का उपयोग करेंगे।

दूसरी ओर अंतरिक्ष में दिशा ज्ञान रात होते ही या सूरज की रोशनी किसी भी ग्रह की छाया में दिशा भ्रम होगा ही,तीसरी तारों की रोशनी में भी यान जब बढ़ेंगे जब वहां कोई माध्यम होगा जब माध्यम ही नहीं तो यान कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर जब तक अंतरिक्ष पार करने की व्यवस्था नहीं तो ग्रहों, पिंडों के वातावरण में कैसे प्रवेश करेंगे और जरूरी है कि उस पिंड या ग्रह के वातावरण में आपका यान उसका ईंधन काम कर ही जाएगा, इसलिए चंद्रमा और मंगल पर पहुंचने की कहानी शिगूफों से ज्यादा कुछ भी नहीं।

आकाशगंगा में किसी भी ग्रह पर जीवन के अस्तितेव को उस पर यदि बादलों का अस्तितेव है तो ही संभव होगा जिसे आप धरती से भी विशाल दूरबीनों से देख सकते हैं। या अंतरिक्ष में स्थापित दूरबीनों के आंकडों से भी ज्ञात किया जा सकता है कि यदि आकाशगंगा के किसी भी पिंड, ग्रह के वातावरण में यदि बादल हैं तो तरलता है और तरलता है तो जीवन अवस्य संभावित है। बेशक यह भी आवश्यक है कि वह पिंड सूर्य जैसे किसी विशाल ऊर्जाशाली ग्रह का ही उपग्रह होगा, जैसा कि पृथ्वी सूर्य का उपग्रह होकर सूर्य का चक्कर लगाती है, वास्तविक ऊर्जा पृथ्वी को भी सूर्य से भी मिलती हा तरलता, वाष्प बनकर बादल बनती है और बादलों का आकाश में संघनन होने के बाद भारी होने पर बरसते हैं वह तरलता पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जिससे वनस्पतियों और जीवों का जीवन चक्र चलता है।

आकाशगंगा में सूर्य जैसे ग्रह हैं जो असीम और विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं तो उनके पृथ्वी के जैसे वातावरण वाले पिंड उपग्रह होंगे और उन उपग्रहों, पिंडों पर उनके वातावरण में दीर्घसमय तक वाष्प का संघनन होकर यदि बादल निर्मित होते हैं, बरसतेतो ही उस ग्रह पर जीवन के

अनुमान लगाया जा सकता है। जो कि दूरबीनों से ज्ञात किया जा सकता है।यदि नहीं तो केवल कोरी बकवास के अतिरिक्त कुछ नहीं। फिर नासा के धूर्त जालसाजों को धरती के अन्य राष्ट्रों में बैठे मूर्खों पर सत्ता चलाने,दहशत बरपाने और अपनी सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए शिगूफे अपनी दुकानदारी के लिए भी तो चाहिए, बस पेश करने का अंदाज होना चाहिए। जहां तक विश्वभर के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टीवी न्यूज चैनल के पत्रकारों का सवाल हैतो 99% मूर्खों को मोटी गिफ्ट और पैसों का लालच दे दीजिए। जंगल के सियारों की तरह हुंआ-हुंआ चिल्लाने और जनता में अपने सिक्के चलाने की आदत है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उससे आम जनता के मूल, वर्तमान और भविष्य पर क्या असर पड़ेगा इन धूर्तों और मूर्खों की बला से।

साप्ताहिक समय माया
पृथ्वी पर हम सब समय माया के पात्री हैं



# मध्यप्रदेश वाणिज्यकर विभाग जालसाजों का अड्डा

# सूचना के आवेदन में जानकारी न देने के षड्यंत्र

## अच्छा वेतन, रिश्वत खोरी, रोमांस सब है राजस्व जाए भाड़ में

**इंदौर।**

म.प्र. वाणिज्य कर में अधिकारी और कर्मचारियों को छठे वेतन मान के पश्चात अच्छा वेतन तो मिलने ही लगा है, फालिों को निपटाने में पहले से कम फिर भी पर्याप्त रिश्वत भी उपलब्ध है अधिकारियों और कर्मचारियों को काम के बदले और अब तो रोमांस के लिए महिला कर्मचारी और अधिकारी भी उपलब्ध हैं तो फिर राजस्व की वसूली तो औपचारिकता ही रह जाएगी। यही हो रहा है चारों तरफ पूरे प्रदेश में, मुख्यालय से लेकर दूर दराज की चौकियों तक पर बेशक, चौकियों के मामले में महिलाओं के समान अधिकार का ख्याल नहीं रखा जा रहा है जो न केवल दुःखद वरन पक्षपातपूर्ण है, आखिकर वहां पर भी पुरुष कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच महिला कर्मियों के रहने से काम और मोटा वसूली का मजा भी सभी के लिए कई गुना हो जाएगा। ट्रक ड्राइवरों को भी लाईन में खड़े रहने में बोरियत नहीं होगी, साथ में काम कर रहे कर्मियों को इस बहाने मोटी टिप भी मिल जाया करेगी सभी प्रकार की।

इन सब कारगुजारियों की हकीकत जानने के लिए सूचना के अधिकार में आवेदन दिए गए तो आयुक्त से लेकर जो बड़ा सख्त बनने का स्वांग भर रहे थे असली चेहरा सामने आ गया, यदि वाणिज्य करायुक्त शैलेन्द्र सिंग यादि वास्तविकता में ईमानदार होते तो अधिकारियों को सबसे पहला निर्देश ही देते कि प्रशासनिक पारदर्शिता लाने के लिए सूचना के अधिकार का अक्षरशः पालन किया जाए, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी तत्काल वाणिज्य कर की साइटों पर अपडेट करते हुए पूरी की जाए, वेट. अधि. उसके हर वर्ष के बजट में किए गए प्रावधानों को तत्काल लोड किया, विभागीय कार्य सम्पन्न करने के लिए विभागीय मेनुअल लोड किया जाए। वैसे जनता को बता दें कि म.प्र. राज्य का गटन हुए 54 वर्ष हो गए परंतु भ्रष्टों के इस विभाग में कार्य मेनुअल ही नहीं बना है। विभाग का। जैसा विभागीय वरिष्ठ सलाहकारों, वाणिज्यकर मंडल व उच्च अधिकारियों को उनकी कमाई के हिसाब से परि पत्र जारी कर काम चलाया जा रहा है। स्वाभाविक है इस विभाग में हर वर्ष रुपए 300 करोड़ का रिश्वत का जो लेन देन होता है, उसका 35 से 40% हिस्सा अकेले इंदौर में बैठे उच्चाधिकारियों से लेकर बाबू तक जीम जाते हैं। इसलिए यहां के उच्चाधिकारी, क्रीमी पोस्ट पाने के लिए रुपए 10 लाख तक आसानी से रिश्वत तक खिलाने में सक्षम हैं। यही कारण है कि सूचना के अधिकार में जानकारी न देने के लिए यहां की एन्टी एवेजन विंग ने सामान्य प्रशासन विभाग म.प्र. शासन से इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्ष बाद भी एक पत्र क्रमां. एफ. 11-39-2008 आर.टी.आई.-1-9 दि. 27-8-09 में जारी करवा लिया, जिसमें इस वाणिज्य कर की एंटीइवेजन विंग को पूरे म.प्र. में जानकारी देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसा कि एंटी एव्जेन विंग अ और ब ने सूचना अधिकार के आवेदन में जानकारी के जवाब में लिखा, पर इन धूर्तों ने इस पत्र की कोई छायालिपि इस पत्रोत्तर में नहीं दी। स्वाभाविक था आवेदक अजमेरा एस.पी. कुमार ने इसे सिरे से खारिज करते हुए अपील फाइल की जिसे अपीलांट अधिकारी और आयुक्त उनके आधार पर अपर आयुक्त सूरज डामोर जो महालालची, भ्रष्ट और निकम्मी है ने लेनदेन कर खारिज कर दिया, वही हाल अपीलांट अधिकारी और आयुक्त के निर्देश पर तीन अपीलें तीनों अपीलांट उपायुक्त संभाग 1,2,3 के विरुद्ध की गई अपीलों में भी किया गया और अपीलें निरस्त कर दी गई।

इस विभाग में एक संभागीय उपायुक्त के अंतर्गत जितने भी सहायक आयुक्त और वाणिज्य कर अधिकारी काम करते हैं, सारे हरामखोर सूचना के अधिकार में जानकारी न देने के लिए एक तरीका निश्चित कर लेते हैं, ताकि जानकारी भी न देना पड़े और कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी हो जाएं और आवेदक इन हरामखोर शूकरों की चाल में उलझ कर रह जाए, यह तरीका पूरे म.प्र. में हर संभागायुक्त के अंतर्गत पिछले चार वर्षों से इन श्वानों द्वारा अपनाया जा रहा है, ताकि आवेदक को पुरानी तारीख में तीस दिन के अंदर जानकारी देने की औपचारिकता भी पूर्ण हो जाए, इसके साथ ही फोटों कापी शुल्क भी इन श्वानों के द्वारा इतना बता दिया या वाणिज्य करारोपण की तरह इतना निर्धारित कर दिया जाता है जैसे पूरा विभाग इनकी बपौती और कानून इनके बापों की जागीर हो, इसकी एक झलक उज्जैन संभाग की ही लें इन उज्जैन संभाग के तीनों वृत्त, एक-एक देवास, शाजापुर, राजगढ़, ब्यावरा में बैठे सारे हरामखोरों ने 06.10.09 में सबने पत्र जारी किए उस पत्र की एक-एक प्रति संभागायुक्त उज्जैन को तो समय पर भेज दी पर आवेदक की प्रति सभी 20-10-09 के बाद ही भेजी, जिसके लिफाफों 23-10-09, 26-10-09 की थी। जवाब की औपचारिकता भी पूरी, चूंकि आवेदक ही पैसा जमा करने नहीं आया, अब कहानी शुरू हुई लिफाफे पर लगी सील की जिसमें इंदौर 20-10-09, 22-10-09, 23-10-09, 26-10-09 की सील लगी थी।

देवास में वाणिज्य कर वृत्त में आया नया वाणिज्य कर अधिकारी को तो पोस्ट का वेतन, बरसती हुई रिश्वत, और साथ में मिली युवा वाणिज्य कर निरीक्षक, जिसे ये हरामखोर कार्यालयीन समय में भी घर पर ले जाकर लोक प्रशासन पढ़ाता है। इसलिए वंदा सित. 09, अक्टूबर 09 में नवम्बर 09 में जब भी कार्यालय गए तो जबकि 8-10 बार कार्यालय गए तो साहब काम से गए हैं फिर धीरे से जब मालूम किया गया तो मालूम पड़ा कि साहब महिला निरीक्षक को सुबह 9 से 11 और दोपहर 1 से 3 घर पर ले जाकर महिला निरीक्षक को लोक प्रशासन पढ़ाते हैं। तब समझ में आया कि रुपए 300/-, 400/- की सूचना के बीस गुना रुपए 61840 का पत्र क्यों नहीं भेजा। हरामखोरों को रोमांस बाजी से फुर्सत मिले जो जानकारी देने की मशक्कत करें, जब कुछ लोगों ने इस अधिकारी साहू से बात की तो विभागीय लोगों को इस श्वान ने भौंकते हुए डांट दिया कि मैं कुछ भी करूं, मैं तुम्हारा बोस या तुम मेरे बोस, फिर मियां-बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, तुम लोगों को क्यों जलन हो रही है, ये है साहू के वक्तव्य जो उसने अपने स्टाफ से डांटते हुए कहे। स्टाफ सदस्यों के अनुसार उसकी पत्नी प्रसव के लिए मायके गई है। इसलिए साहब विभाग की महिला निरीक्षक को घर ले जाकर अपनी पत्नी की अनुपस्थिति में ऐसा लोक प्रशासन, आनंद सिखा रहे हैं, सूचना के अधिकार में रुपए 300/-,400/- की जानकारी को अपनी जागीर समझ कर रुपए 61840 पत्र क्रमांक सी.टी.ओ./1/सामान्य 09/937 दिनांक 6.10.09 इंदौर डाक घर की सील 23.10.09 इस प्रकार भेज कर मांग रहे हैं। जैसे आवेदक इनकी जागीर का देनदार हो। ऐसे रोमांस के लिए इस विभाग में बैठे शूकरों, भ्रष्टों की फौज जवाब दे रही है।

## समयमाया को...

पेज 8 का शेष

जिस तरफ श्री अजमेरा ने दृष्टिपात किया जनहितों के लिए जान दांव पर लगाकर बड़े-बड़े महारथियों जो अपने आपको खुदा समझते थे कलम बेशक इसे वो अपनी नहीं वरन् उस परम सत्ता का ही आशीर्वाद मानते हैं और उसी की प्रेरणा और शक्ति का माध्यम समझते हैं। फिर समयमाया ने विश्व की जनता के हितों की ही नहीं वरन पृथ्वीवासी सहस्त्रों मूकजीवों, हरियाली वनों, वृक्षों के हितों को भी अपनी ही जंग का हिस्सा मान जागृति लाने के प्रयास किए हैं। बेशक बेलाग लपेट, सपाट भाषा का प्रयोग भ्रष्टों को न केवल क्षेत्रीय स्तर पर, प्रदेश की राजधानी, वरन देश की राजधानी में भी सीधे ही प्रहार किए हैं।

यही कारण है कि समयमाया के नाम से पहले मिलते जुलते नामों के अनेकों समाचार पत्र बाजार में आए जिसमें सहारा समय समयगति आदि थे। अब समायमाया डाट काम या समयमाया को लॉग ऑन करने पर सीधे ही गूगल पर साइट जाती है और साइट खोलने वालों को हमारी साइट पर ले जाने की अपेक्षा 422 विभिन्न साइटों की जानकारी देता है, परंतु समयमाया राष्ट्रीय समाचार पत्र के नाम से वहां मात्रा एक लाईन ही दिखती है, जबकि अश्लीलता के साथ अनेकों साइटों पर समयमाया के नाम से यहां तक कि मां-बेटे की प्रणय लीला तक का भौंडा प्रदर्शन अमेरिकी साइटों के साथ ही प्रदर्शित किया जा रहा है।

बेशक यह श्री अजमेरा के समाचार समयमाया पत्र की ख्याति न केवल राष्ट्र में वरन खासतौर पर अमेरिका में भी किस हद तक उस पर अमेरिकी साइटों ने कार्टून तक बना कर डाल रखे हैं।ताकि आम नेट उपभोक्ताहमारी साइटों तक न पहुंचे और अमेरिका उसके नाटो-चमचों की दुनिया भर में किए जा रहे कुकर्मों की सच्चाइयां न जान सके।

इस अमेरिकी गूगल की इस भौंडी चाल और छल कपटों से हमारे पवित्र उद्देश्य, राष्ट्र और विश्व के कल्याणकारी भविष्य के मिशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितने हमें खलनायक, बदनाम करेंगे उतना ही नाम गहरे पैठ करेगा, देश और दुनिया की जनता के दिलों में जनता सच्चाई और सर्वकल्याण नायकल को भले ही देर से अब हमारे सच को देश और दुनिया की जनता गंभीरता से स्वीकारेगी, ये गूगल वालों की 42-45 पेजों की 422 खोज परिणाम ही वास्तविकता में विश्व के अखिल मानव समाज में हमारे अस्तित्व की सार्थकता को सिद्ध करेंगे।

वर्तमान में सच तो ये है कि हमें हमारे ही मोहल्ले और इंदौर नगर में कोई नहीं पहचानता, प्रदेश औरदेश की जनता की बात तो बहुत दूर इसके विपरीत इसके लिए हमारी ओर हमारे पाठकों की ओर से धन्यवाद।

## खाद्य सुरक्षा के नाम...

पेज एक का शेष

स्वाभाविक है किसान के खेत से सब्जियां, अनाज, खाद्यान्न दलहन, तिलहन तक जब सब बहुराष्ट्रीय कंपनी ही खरीदेंगी, अच्छा माल पूरी दुनियाभर का माल बंदपैकेटों में मनचाही कीमतों पर देश मेंतो जनता देख भी नहीं पाएगी कि पैकेट के अंदर क्या और कैसा है, जो वो आईटीसी, रिलायंस, हिन्दुस्तान लीवर, नेस्ले बचेंगे वहीं खरीदना पड़ेगा फिर शक्कर रुपए 100 प्रति किलो, गेहूं पपले वर्ष 25, दूसरे वर्ष 50, तीसरे वर्ष अच्छा गेहूं और उसका आटा 100 रुपए किलो भी बिकेगा। तो खाना पड़ेगा। इन बहुराष्ट्रीय कंपनी के चंगुल में पूरी तरह से जकड़ जाने के बाद ये यहां की आबादी के 80% पुरुषों को नपुसंक बना डालेंगी। जैसा कि पैप्सी, कोक, साफ्ट ड्रिंक में कीटनाशक हल्दी, धनिया, जैसे मसालों में चावल की भूसी, चाकलेट, बिस्कुट में केक आईसक्रीम में जिलेटिन आदि मिलाकर जनता को डिब्बा बंद पैकेटों में परोसा जा रहा है। 30 वर्ष के नवयुवा भी हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। हर प्रकार से कांग्रेसी डकैत, इस तरह से सफेदपोंश तरीके से जनता का शोषण कर अपनी सल्तनतें बनाएंगे।

### शास.अधिकारियों और शासन को फायदे

1. प्रधानमंत्री, अन्य सभी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों से लेकर अन्य सभी मंत्रीयों जो राज्यों में होंगे, वेतन के अतिरिक्त वेतन मिलेगा, ताकि वो इन बहुराष्ट्रीय कंपनी की स्वयं गुलामी करें और जनता पर जुर्म ढाएं तो ये श्वान उन पर भौंके नहीं और पालतू श्वानों की तरह अपने आकाओं को देखते ही दुम हिलाने लगे, उन्हें उनके हितों की सुरक्षा करें।

2. जब मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री गुलाम होंगे, तो इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के मुखैरों की तो बिसात ही क्या? ये तो इस राष्ट्र के असली मालिक हैं। इनको भी वेतन के अतिरिक्त वेतन मिलेगा तो ये भी सारी शासकीय मशीनरी के उनके चरणों में बिछाकर स्वयं भी चरणदासी करते रहेंगे।

3. सत्ताधीशों, प्रशासन ने इन आईटीसी, रिलायंस, यूनिलीवर, नेस्ले, मेकडानल्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के पालतू श्वानों की तरह महीना मिलेगा, साथ ही पैकेट खाद्य पदार्थ भी मुफ्त में श्वानों को पहुंचा दिया जाएगा। अच्छी गुणवत्ता वाला और बाजार में कहां हैं? वहां के रहवासियों का स्तर क्या है, वहां किस वर्ग का कितनी कीमत का माल बिकेगा, यह आन लाईन प्रबंधन कंपनी अपने मुख्यालय से आंचलिक और क्षेत्रीय कार्यालय निश्चित करेंगे, खाद्य की गुणवत्ता जो पैकेट बंद होने के कारण देखी नहीं जा सकेगी, रंगों से, वर्गों से दरों पर मिलेगी, गंदी बस्ती में एक दम मिलावटी निम्न स्तरीय खाद्य बिकेंगें, कंपनी की दरों पर।

4. धारा 65 में ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से मरने वालों को अंतिम क्षति पूर्ति रुपए 5 लाख मिलेगी भी तो रुपए 1 लाख सिद्ध करने में कि उसके खाद्य से ही मृत्यु हुई है। लाख रुपए सरकारी, रिश्वत खोरी खर्चों में खत्म हो जाएंगे आने-जाने कार्रवाई करने और फैसले को प्राप्त करने में समय गुजर जाएगा, फिर जो बच्चे बढ़े होंगे वो इन बहुराष्ट्रीय कंपनी की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए एकजुट होना शुरू करेंगे। हंर मौत पर भी अधिकारी मोटी कमीशन डकारेंगे।

5. इन कंपनियों के आने से राजनीतिज्ञों को महीने के टुकड़ों के साथ चुनाव लड़ने, दंगे-फसाद करवाने, बड़े-बड़े कांडों को अंजाम देने विरोधी कंपनियों के खेतों की खड़ी फसलों को आग लगवाने, उनका माल लुटवाने आदि के लिए सौदेबाजी का भी मोटा धन मिलेगा।

6. बिजली, पानी, सड़कों आदि पर जो इन कंपनियों के अधिकार में होंगी, मनचाही कानून वसूली होने के साथ इन पर भी राशनिंग और कालाबाजारी होगी, जिस पर मोटा कमीशन मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को मिलेगा, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी खाद्य से मिले लाभांश से कई गुना कमाई करने के लिए बिजली, पानी, सड़कों, कृषिभूमि तक पर कब्जा जमाएंगी जैसा कि रिलायंस कर रहा है।

### इसके लागू होते ही संभावित परिणाम

1. छोटे-मोटे व्यापारी, सब्जीवाले, ठेलेवाले, दूध वाले लघु उद्योग इकाइयों में कार्यरत लोग, इकाइयां बंद होने से पूरे देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

2. ग्रामीणों की इस बेरोजगारी से उत्पन्न समस्या और भूखमरी से मरने वालों को रोकने के लिए गरीबी रेखा से नीचे वालों को सस्ता गेहूं, चावल, देना इसीलिए शुरू किया। ग्रामीण रोजगार गारंटी में 100 दिन काम की घोषणा भी उसी का हिस्सा है। गांवों में बगावत रोकने और बहुराष्ट्रीय कंपनी के हितों की सुरक्षा और उन्हें बंधुवा मजदूर दिलवाने की व्यवस्था है। जहां बगावत का पहला बिगुल बजता है। फिर भी इन बहुराष्ट्रीय कंपनी के विरुद्ध भीड़ वहीं से इकट्ठा की जाएगी और होगी।

3. सबसे ज्यादा आकांत गरीबी से ऊपर, निम्न मध्यमवर्गीय और मध्यमवर्गीय तक को दो वक्त का भोजन 6 सदस्यी परिवार को भी अच्छा भोजन नहीं मिल सकेगा।

4. बेरोजगारी गरीबी रेखा से ऊपर, निम्न मध्यमवर्गीय से उच्च मध्यमवर्गीय नौकरी पेशा सब में ही आएगी। सबसे ज्यादा इस गुलामी का देश उन्हीं को भोगना पड़ेगा।

5. गरीबी रेखा से ऊपर उच्च मध्यमवर्गीय बेरोजगारी सभी प्रकार के अपराधों को बढ़ावा देगी। वैश्यावृत्ति से 25% जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाएगी, यूरोप, अमेरिका और बहुराष्ट्रीय कंपनी भी यही चाहती है और सत्ताधीशों को यही चाहिए।

6. बहुराष्ट्रीय कंपनी के बीटी जीएम बीजों से लाखों किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अब व्यापारियों, लघु उद्योगों, छोटे व्यावसायियों और कम और मध्यमवर्गीय आय वालों की बारी है। इस अधि. के लागू होने के तीन महीने में ही आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ने लगेगी।

7. नक्सवाद धीरे-धीरे पूरे देश में पैर पसारेगा। उसमें फिर पढ़े-लिखे उच्च शिक्षित, बेरोजगार भी शामिल होकर सत्ताधीशों, पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनीयों के अधिकारियों के अपहरण, लूट और हत्या करेंगे।

8. इन नक्सलियों, डकैतों का उपयोग, सत्ताधीश प्रशासन और राजनीतिज्ञ अपने-अपने तरीके से जैसे अभी कर रहे हैं। बाद में भी खुल कर करेंगे। उन्हें संरक्षण देंगे, यही हाल आतंकवादियों का भी होगा।

9. सत्ताधीशों और प्रशासनिक अधिकारी अपनी अय्याशी और मौजमस्ती में डूबे रहेंगे। पाकिस्तानी आतंकवादी, चीनी, सेनाएं और चीन इनका भरपूर फायदा उठाएंगे। युद्ध करके काश्मीर को अलग कर लेंगे और चीन भारत में काफी अंदर तक घुस जाएगा और कब्जा करता रहेगा। तब भी अभी जैसे ही कांग्रेसी गिरोह चिल्लाएगा नहीं सब शांति है। जबकि अभी हर रोज अंदर घुस ही रहा है। और कांग्रेसी अय्याश कमीशन खोर शांति-शांति चिल्ला रहे हैं।

10. बहुराष्ट्रीय कंपनी किसानों को उन्हीं की जमीनों पर मजदूर बना कर काम लेगी और तैयार फसल अपने हिसाब से अपनी कीमतों पर जनता को बेचेगी। लागू होने के 1-2 वर्ष में मंडियों और बाजारों की पूरी व्यवस्था शापिंग माल और आईटीसी, रिलायंस, यूनिलीवर, नेस्ले, मेकडॉनल के हाथों में सिमट जाएगी। चाय रुपए 20 से लेकर रुपए 50 प्रति कप सन 2020 तक ही पहुंच जाएगी।

## म.प्र. स्वास्थ्य विभाग कदम-कदम भ्रष्टाचार

# ऊपर से नीचे तक जालसाजियों का अम्बार

**भोपाल।**

म.प्र. स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय से लेकर दूरदराज के गांवों में कार्यरत प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग में सफेदपोश शासकीय धूर्त डकैतों का बोलबाला है गरीब जनता के स्वास्थ्य के लिए सरकार घोषणाएं तो ढेर सारी करती है परंतु विभाग की वास्तविकता के बारे में न केवल जनता जानता ही वरन प्रदेश भर के सैकड़ों समाचार पत्रों, क्षेत्रीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय दूरदर्शनीय समाचार श्रृंखलाओं में भी ये बेशर्म, धूर्त, मक्कार निकम्मे सदाचर्चा में बने रहने की इनकी फेहरत है।

इसके संबंध में श्री अजमेरा ने म.प्र. स्वास्थ्य संचालनालय के अनेकों पत्र सूचना के अधिकार में प्रस्तुत किए हैं, परंतु जवाब अधिकांश में नहीं मिला है, कई मामलों में पेशियों धूर्तों के सूचना आयोग में भी करवाई गई अधिकांश में जानकारियां नहीं मिली, इसकी शिकायत के विपरीत सूचना आयोग भी कुछ नहीं कर पाया। इस विभाग में कुछ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के विरुद्ध जांचे लंबित और कुछ में निर्णय हो जाने के बाद भी पदोन्नतियां दे दीं गई जिनका अनुमोदन म.प्र. लोकसेवा आयोग ने भी नहीं किया। एक पत्र पाठकों के लिए प्रस्तुत है-

### संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश

**क्रमांक.4/शिकायत/डी.ई.2/ 2008/ 207** **भोपाल दिनांक 21/1/08**

प्रति, अपर सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, भोपाल मध्यप्रदेश

**विषयः** संयुक्त संचालक के पद पर पदोन्नतियां हेतु विचार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों की विभागीय जांच की जानकारी के संबंध में।

**संदर्भः-** आपकी नोटशीट क्रमांक 3872/07/17 मेडि-1 दिनांक 22.12.07

उपरोक्त विषयांन्तर्गत आपकी नोटशीट दिनांक 22.12.07 में संलग्न सूची अनारक्षित वर्ग की सरल क्रमांक 1 से 27 तक तथा अ.जा. संवर्ग की 1 से 4 तक और अ.जा.ज. संवर्ग की सरल क्रमांक 1 से 5 तक संयुक्त संचालकों के पद पर पदोन्नतियां हेतु विचार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच/लोकायुक्त जांच ई.ओ. डब्ल्यू संबंधी जानकारी चाही गई, प्रथम श्रेणी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही शासन स्तर से भी की जाती है। संचालनालय में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार जानकारी निम्नानुसार है-

| क्र. | वरिष्ठता सूची क्र. | संवर्ग | विभागीय जांच/लो.आ. जांच/ई.ओ. डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| 01. | 01 | सामान्य | डॉ. श्रीमती पुष्पा गुप्ता के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित है। जो संचालनालय में विचाराधीन है। |
| 02. | 03 | सामान्य | डॉ. राजाराम जड़िया के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित है। संचालक के पत्र दिनांक 28.7.06 को आरोपपत्र जारी किए गए। |
| 03. | 04 | सामान्य | डॉ. के.के. विजयवर्गीय के विरुद्ध शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ.13-2/07/17 मेडि-1, दिनांक 26.6.07 द्वारा दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं दो बार अलग-अलग प्रकरणों में एवं प्रकरण संचालनालय स्तर पर विचाराधीन है। |
| 04. | 11 | सामान्य | डॉ. शरदचंद्र पंडित इनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ.13-2/07/17 मेडि. 1, दिनांक 26.6.07 द्वारा दिनांक 7.1.2005 को आरोपपत्रादि जारी किए गए एवं प्रकरण संचालनाय स्तर पर विचाराधीन है। विभागीय जांच/ लोकायुक्त जांच संस्थित है। |
| 05. | 15 | सामान्य | डॉ. के. एम.ओझा, सी.एम.ओ. भिण्ड को संचालनालय के पत्र क्रमांक 1946/दिनांक 27.12.07 सेल.2 द्वारा इनके विरुद्ध आरोप पत्रादि जारी किए गए हैं एवं इनके विरुद्ध लोकायुक्त जांच चल रही है। |
| 06. | 16 | सामान्य | डॉ. राजेंद्र सिंह के विरुद्धशासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ.13-2/07/17 मेडि-1 दिनांक 26.6.07 द्वारा दो वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। एवं प्रकरण संचालनालय स्तर पर विचाराधीन हैं। इनके विरुद्ध लोकायुक्त जांच चल रही है। |
| 07. | 17 | सामान्य | डॉ. हीरालाल मिश्रा इनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा दिनांक 20.9.2006 को आरोपपत्रादि जारी किए गए। |
| 08. | 19 | सामान्य | डॉ. वी.के. चौबे इनके विरुद्ध कारण बबताओ नोटिस जारी किए गए हैं। लोकायुक्त जांच संचालनालय स्तर पर प्रचलन में है। |
| 09. | 25 | सामान्य | डॉ. श्रीमती एस.पी. चतुर्वेदी के विरुद्ध शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ.13-2/07/17 मेडि-1 दिनांक 26.6.07 द्वारा दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं एवं प्रकरण संचालनालय स्तर पर विचाराधीन है। |

**इन बिन्दुओं के संबंध में जानकारी निरंक मानी जावे। सरल क्रमांक 2,5,6,7,8,9,10,12,13,14,18,20,21,22,,23,24,26,27**

**अ.जा. वर्ग**

| क्र. | वरिष्ठता सूची क्र. | संवर्ग | विभागीय जांच/लो.आ. प्रकरण/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेक्षण ब्यूरो |
|---|---|---|---|
| 1. | 28 | अ.जा. | डॉ. श्रीमती सी.के. ठाकुर इनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। शासन द्वारा दिनांक 2.5.2003 द्वारा आरोप पत्रादि जारी किए गए हैं एवं प्रकरण संचालनालय स्तर पर विचाराधीन है। लोकायुक्त जांच चल रही है। |
| 4. | 32 | अ.जा. | डॉ. ईश्वललाल मेहरा, इनके विरुद्ध शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ. 13-2-/07/17 मेडि-1, दिनांक 26.6.07 द्वारा दो वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनके विरुद्ध विभागीय जांच संचालनालय स्तर पर चल रही है। |

**सरल क्रमांक 2,3 बिन्दुओं के संबंध में जानकारी निरंक मानी जावे**

**अ.जा.ज. संवर्ग**

| क्र. | वरिष्ठता सूची क्र. | संवर्ग | विभागीय जांच/लो.आ. प्रकरण/ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेक्षण ब्यूरो |
|---|---|---|---|
| 35. | 35 | अ.जा.ज | डॉ. मोहनसिंह इनके विरुद्ध संचालनालय के पत्र क्रमांक 202/ दिनांक 21.11.2008 डी.ई.1 द्वारा आरो पत्र जारी किए गए हैं। |
| 36. | 36 | अ.जा.ज. | डॉ. जी.एस. रावत इनके विरुद्ध शासन द्वारा उनके पत्र क्रमांक एफ. 13-2/07/17 मेडि-1, दिनांक 26.6.07 द्वारा दो वेतनवृद्धि रोकने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं एवं प्रकरण संचालनालय स्तर पर विचाराधीन है। |
| 37. | 37 | अ.जा.ज | डॉ. सी.बी. सोलंकी इनके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है। शासनद्वारा 29 मार्च 03 को आरोपत्रादि जारी किए गए। प्रकरण वर्तमान में संचालनालय स्तर पर विचाराधीन है। |
| 38. | 38 | अ.जा.ज | डॉ. आर.एस. डुडवे, इनके विरुद्ध शासन के पत्र क्रमांक एफ. 13-2/07/17 मेडि-1 दिनांक21.12.2004 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 1 प्रकरण संचालनालय स्तर पर विचाराधीन हैं। |

**अ.जा.ज. संवर्ग बिन्दु क्रमांक 34 की जानकारी निरंक मानी जावे।**

**अपर संचालक (शिकायत), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश**
**एस.आर. नाईक, अनुभाग अधिकारी, म.प्र. लोकसेवा आयोग, इंदौर**

**इस आदेश के विपरीत लोककस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने धनका मोटा लेनदेन करके डॉ. (श्रीमती) पुष्पा गुप्ता और डॉ. के.के. विजयवर्गीय को उज्जैन व इंदौर का संचालक बना दिया, देखें आदेश की प्रति.**

### मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय

//आदेश//

**भोपाल दिनांक, 8/09/2008**

क्रमांक एफ-1-08/2006/सत्रह/मेडि-/एक ग़ाज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ उपसंचालक को संयुक्त संचालक के पद पर वेतनमान रुपए 12,000-375-16500 में पदोन्नत करते हुए उन्हें कालम-04 में दर्शाए गए स्थान पर कार्यग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ किया जाता है-

| क्र. | चिकित्सा अधिकारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना का नाम | पदोन्नति उपरांत पदस्थापना का स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | डॉ. (श्रीमती) पुष्पा गुप्ता प्रभारी संयुक्त संचालक, | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन | संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं उज्जैन |
| 2. | डॉ. के.के. विजयवर्गीय | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रभारी संयुक्त संचा., स्वा. सेवाएं इंदौर | संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं इंदौर |

2/- प्रमाणित किया जाता है कि इस पदोन्नति के लिए म.प्र. लोकसेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियम/निर्देशों का पालन किया गया है।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार**
**(जयश्री कियावत), उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन**

प्रतिलिपिः-
1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, की ओर माननीय मंत्रीजी को अवगत कराए जाने हेतु अग्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोकस्वास्थ्य एवं परि. कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल।
5. समस्त संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।
6. संभाग आयुक्त जिला-उज्जैन/इंदौर
7. कलेक्टर जिला-उज्जैन/इंदौर
8. उपसंचालक जनसम्पर्क भोपाल।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी लोक स्वा. एवं परि.क. विभाग
10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय इंदौर/उज्जैन
11. संबंधित के नाम से----------
12. स्टॉक फाईल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

### संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश

**पृ. क्रमांक-4/ शिकायत/सेल-2/इंदौर 09/339** **भोपाल दिनांक 7/2/09**

//आदेश//

डॉ. के.के. विजयवर्गीय तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी वर्तमान में संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाएं इंदौर को वित्तीय वर्ष 2006-07 में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 14 के अ.ब.स.द. का पालन न कर वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 10(3) के अंतर्गत संचालनालय के पत्र क्रमांक/4/शिका./सेल-2/15497 दिनांक 09.07.2008 द्वारा आरोप पत्र जारी किए गए हैं। डॉ. के.के. विजयवर्गीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं इंदौर ने प्रतिवाद उत्तर दिनांक 30.10.2008 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर परीक्षणोंपरांत संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण मैं, डॉ. मनोहर अगनानी, स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश डॉ.के.के. विजयवर्गीय,संयुक्तसंचालक स्वास्थ्यसेवाएं इंदौर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 10(3) के अंतर्गत रुपए 6,60,660/- (छह लाखसाठ हजार छह सौ साठ रुपए) की वित्तीयहानि की वसूली करने की शास्ति से दण्डित किया जाकर प्रकरण समाप्त करता हूं।

**(डॉ. मनोहर अगनानी), स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश**

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
1.सचिव मध्यप्रदेश शासन, लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. अपर संचालक (गोपनीय/अविज्ञप्त शाखा) स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर संभाग, इंदौर की ओर उनके पत्र क्रमांक/शिका./08/12673, दिनांक 30-10-2008 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यालय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाएं इंदौर को निर्देशित किया जाता है कि डॉ. के.के. विजयवर्गीय,संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं इंदौर के वेतन में नियमानुसार वसूली करें।
5. डॉ. के.के. विजयवर्गीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाएं, इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद पर वर्तमान में विराजमान डॉ. महेश कुमार पाटनीको ही लें इनके विरुद्ध भी जांचे और शासन के धन की वसूली लंबित होनेके कारण इन्हें शासन के आदेश से इंदौर का प्रभार नहीं सौंपा गया वहां पर डॉ. पाटनी के पहले डॉ. मुद्गल प्रभारी थे, उन्हें हटाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं मिला तो उन्हें मलेरिया के प्रकरणों में उलझा कर निलंबित कर दिया गया, जबकि डॉ. मुद्गल विभाग मेंह एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि ईमानदारों को सीधे नहीं हटाया जा सकता तो धूर्तों ने उन्हें निलंबित करवा कर बिना आदेश के ही डॉ. पाटनी को इंदौर का प्रभारी बना दिया, जबकि प्रभारी अधिकारी न तो कोषालय से किसी प्रकार के लेनदेन का अधिकार रखता है, नही न्यायालयीन प्रकरणों में, जबकि मात्र मौखिक आदेश का बहाना लेकर डॉ. के.के. विजयवर्गीय ने पाटनी को प्रभार सौंप दिया, स्वाभाविकहै शासकीय कोषालय से लेन-देन के लिए प्राधिकृत नहींहै। और न ही वो किसी वैधानिक न्यायालयीन प्रकरणों पर उपसंचालक खाद्य एवं औषधि विभाग के प्रकरणों में हस्ताक्षर कर प्रकरण न्यायालयों में प्रस्तुत करने के पात्र हैं। इसके विपरीत न केवल डॉ. पाटनी ने सारे प्रकरण हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही वो खाद्य एवं औषधि विभाग के खाद्य निरीक्षकों को खाद्य के नमूने लेने के लिए पर्चियोंपर हस्ताक्षर करने के और नमूने लेने की आज्ञा देनेके भी रुपए 2से 5हजार प्रतिमाह मांगते हैं। स्वाभाविक है खाद्य निरीक्षक भी हर नमूने लेने के बाद नमूने लेने के बाद अच्छा माल के नमूने में बदलने के लिए इंदौर में हर प्रकरण में रुपए 10से 25 हजार वसूलते हैं। इंदौर के खाद्य निरीक्षक सचिन लोंगरिया ने हाल ही में नवम्बर-दिसम्बर में लगभग 10 प्रकरणों में नमूने बदलने के लिए लाखों रुपए की वसूली की।

इंदौर के स्वास्थ्य विभाग में विधि सलाहकार के पद पर बैठा सुनील चड्ढा जो तिलहन संघ से प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग में 6-7 वर्षों से है। स्वास्थ्य विभाग में रहकर धन कमाने और इश्क लड़ाने के लिए कुख्यात हो चुका है। यहां पर संविदा नियुक्ति पर चार्टर्ड एकाउंटेंट के पद पर बैठी सुश्री मनीषा अग्रवाल ने भी इसकी बदमीजी के आरोपों की शिकायत की है। जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आर.सी.एच. में बैठी डॉ. मोनिका मंडलोई के साथ सारे दिन बैठकर ये कुछ भी करे कोई आपत्ति नहीं पर इन्होंने मुझसे संबंध बनाने के लिए न केवल प्रताड़ित किया बल्कि ऐसे गंदे शब्दों का प्रयोग किया, जिसे मैं आवेदन पत्र में लिख नहीं सकती। इस सुनील चड्ढा की पत्नी चूंकि डेली कालेज में काम करती है,स्वाभाविक है वहां सभी उच्च अधिकारियों, मंत्रियों की संताने पढ़ती हैं। उसने इस विभाग में टिका रखा है। जबकि कोई भी कर्मचारी अधिकारी अधिकतम 4वर्ष से ज्यादा किसी विभाग में काम नहीं कर सकता,ये हरकतें इस विभाग की पी.एच.सी. से लेकर मंत्रालय तक की गतिविधियों का स्थाई हिस्सा है।

**भोपाल को ही लें** श्रीमती धनीला नारायण उपसंचालक आई.ई.सी. की मुख्यालय में प्रभारी है। इन्होंने डॉ. मनोहर अगनानी को खुश करने के लिए सरकारी खर्चों पर 28.10.09 को एक होटल में 26.10.09 को एक पार्टी दी थी। जालसाजियां, भ्रष्टाचार, यौनाचार, स्वास्थ्य विभाग के स्थाई रोग हैं। जिनकी दवा किसी के पास नहीं, फिर डॉक्टरों की ये फौज प्रदेश का स्वास्थ्य कैसे ठीक कर सकती है।

### लोक स्वा. यां. विभाग के कां.यं. अजय पर लोकायुक्त का छापा

# भ्रष्ट आई.ए.एस., आई.पी.एस., आई.एफ.एस. पर क्यों नहीं छापे?

### कमजोर कड़ी कौन? जिस पर दांव चले और नाम, दाम भी हो

इंदौर में निवासरत धार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के का.यं. अजय श्रीवास्तव के यहां छापा पड़ा और रुपए 10 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति पकड़ी गई। इसके विपरीत बंदा सरकारी निवास में इंदौर में भी रहता है और सरकारी निवास में ही धार में निवास करता था। इस छापे को अंजाम देने में उसके सामने रहने वाला मुख्य अभियंता डामोर की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिसकी पत्नी श्रीमती मंजू डामोर पदोन्नत आई.ए.एस. है, जिसने हाल ही में अपनी पूर्व पत्नी के बेटी की शादी की है जो स्वयं भी दोनों ही करोड़ों रुपए की सम्पत्ति के धार, झाबुआ और इंदौर में भू-मालिक हैं। छापे के कारणों और उद्देश्यों की श्रृंखला विस्तृत है उक्त कां. यं. प्रमुख अभियंता सुधीर सक्सेना के खेमे का था, दूसरा वो होंडा सिटीकार में घूमेगा उसका वरिष्ठ सरकारी जीपों में कैसे हजम होगा, फिर वो हटता तो मुख्य अभियंता अपने खास लोगोंको धार में बैठा पाते।

वैसे ऐसे अभियंताओं जिनमें वर्तमान में अधीक्षण यंत्री बना बैठा अजय दाहिमा इसके पास भी 20-25 करोड़ की सम्पत्ति है एक प्लास्टिक फैक्ट्री है। करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष का चंदन उसने विभाग की ड्रिलिंग मशीनों के रखरखाव के नाम से ही लगाया है ऐसेही का.यं. लो. नि.वि. संभाग दो इंदौर एन.पी. राने हैं, जिनके पास भी ऐसे ही 15 से 20 करोड़ की सम्पत्ति है।

इसके विपरीत लोकायुक्त सी.बी.आई., आयकर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कभी भी बड़े से बड़े भ्रष्ट, अरबों रुपए की सम्पत्ति के मालिक इंडियन एव्यूसिंग सर्विस बनाम आई.एम. सेफ बनाम आई.ए. एस., दूसरा इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन सर्विस बनाम आई.पी.एस. ये भी हर कदम सैकड़ों किस्म के अपराधियों को बचाते हुए पैसा कमाते हैं। इंदौर को ही लें इंदौर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में पूर्व में माहेश्वरी रहे और वर्तमान में श्री निवास आ गए क्या पूरा सट्टा बंद हो गया, वैश्यावृत्ति के अड्डे बंद हो गए, या पूरे शहर में फैला नशे का कारोबार बंद हो गया? फिर क्राइम ब्रांच में बैठा हर उपनिरीक्षक सहायक निरीक्षकतक करोड़पति कैसे है। जितने भी पुलिस अधिकारी इंदौर मेंरहकर गए हैं सबके कितने मकान,फ्लेट न केवल इस शहर में हैं वरन उस पर थानों की पुलिस भी पहरा देती है। अधिकांश की बसें, ट्रक, किसी के नर्सिंग होम, किसी के स्कूल चल रहे हैं। आखिर लोकायुक्त, आयकर, आर्थिक अन्वेषण को ये क्यों नहीं दिखता, आखिर स्कूल चलाने, नर्सिंग होम खोलने और चलाने, बसे चलवाने हर शहर में ये जहां भी जाते हैं मकान, फ्लैट के लिए आखिर करोड़ों रुपए कहां से, कैसे आए? किसी को नहीं दिखता।

यहां अपराधी को फरियादी और फरियादी को अपराधी बनाने का खेल पैसे के दम पर चलता है। यहां कांस्टेबल से लेकर आईपीएस तक गिरगिट की तरह क्षणभर में रंग बदलने के आदि होते हैं। इंदौर में ही मा.प्रबंध संस्थान की प्राध्यापक अमृता पांचोली हत्याकांड में हत्यारे प्रबंधक केही छात्र हैं और किसी दवा कंपनी के मालिक की औलाद हैं, जिन्हें मालूम है कि खून के दाग किस रसायन से साफ हो जाते हैं। चूंकि प्रोफेसर अकेली थी उम्र 32 वर्ष थी हवस मिटाने के लिए लड़कों को ले जाती ती, उस दिन भी लड़कों को लेकर गई पहले मैं, पहले मैं झगड़ाहु और उसकी चालबाजियों से त्रस्त प्रबंधन के छात्रों ने हत्याकर दी। प्रबंधन के वो छात्र करोड़ पतिबाप के बेटे थे, रातों रात पुलिस को रुपए 25-50 लाख का आफर दिया, उन्होंने बेकसुर ड्राइवर जो शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पर होने क बाद भी कमजोर कड़ी होने के कारण सारा अपराध उसके सर मढ़कर इतिश्री कर ली गई। पुलिस इस खेल की विशेषज्ञ है। बड़े अपराधी माफिया के साथ रासलीला, रंगलीला, अर्थलीला इन्हीं के संरक्षण में पलती है। अधिकांश आई.पी.एस. अरबपति होते हैं। परिवार के हर सदस्य के नाम करोड़ों की सम्पत्ति होती है। पास के साथ दूर के भी नहीं तो पाले हुए कुत्ते बिल्लियों के नाम से भी सम्पत्ति खरीद की जा जाती है। पर लोकायुक्त सीबीआई, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो जिसमें सबमें ही पुलिसिये बैठे होते हैं अपने भाई बंदों की पूरी रक्षा करते हैं।

यही हाल भारतीय वन (मिटाओ, लूटो, खाओ) सेवा अर्थात इंडियन फारेस्ट सर्विस के हैं ये हरामखोर शासन के पैसे की बंदरबांट करने के साथ जंगलों को कटवाकर बिकवाने से लेकर वन भूमि को जालसाजियों से बेचने,कब्जे करवाने से लेकर किराए पर खेती करवाने तक से धन कमाते हैं। सारे वन इनके क्षेत्र के इनकी बपौतियां होती हैं माफियाओं से मिलकर कीमती वृक्षों की कटाई करवाने, वनोषधियों, वनोत्पादों को बिकवाने, चोरी करवाने, वन पशुओं के शिकार करवाने, खाले, दांत, चमड़ा बिकवाने तक में ये अपनी भूमिका अदा करते हैं। वीरप्पनों, की फौज इनकेही संरक्षण में पलती है। सबही करोड़पति होते हैं। जब छापे पड़ने की कार्यवाही होती है तो कमजोर कड़ी के रूप में वो रेंजरों, वनपालों, वनरक्षकों पर उनके ही विरुद्ध सारे प्रकरण लादे जाते हैं। इन करोड़पति अरबपति इंडियन फारेस्ट ईटिंग सर्विस के अधिकारियों पर भी लोकायुक्त, आर्थिक अपराध, आयकर आदि के छापे नहीं पड़ते, क्योंकि ये भी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी हैं ये भी अपने आप को वनों के खुदा मानते हैं।

वैसे लोकायुक्त, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो में होते तो सारे भ्रष्ट अधिकारी ही हैं। आप एक शिकायत कर दीजिए प्रकरण पंजीबद्ध हो न हो, राज्य सेवा के चुने हुए अधिकारियों से चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो, तहसीलदार, पटवारी, विक्रय कर बनाम वाणिज्यकर, कृषि, लोकनिर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय, ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा, नगर निगमों, पालिकाओं, आर.टी.ओ., स्वास्थ्य विभाग,सहकारिता, जल संसाधन विभाग, महिला बाल विकास, खनिज, पशु चिकित्सा आदि सभी विभागों में बैठे राज्य सेवा से चुनकर आए अधिकारी जिनका कोई संगठन नहीं उनके विरुद्ध ही लोकायुक्त कम से कम महीने की वसूली तो इस शिकायत के आधार पर शुरू कर ही देगा क्योंकि उनका कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं,स्वाभाविक है उनकी आवाज उठाने वाला या लड़ने वाला कोई नहीं, ये कमजोर कड़ी हैं। तो इन्हें ही लोकायुक्त, आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो, आयकर सब ही छापे मारते, वसूली करते और भ्रष्टाचार सिद्ध करते हैं।

## देश की धरती...

पेज एक का शेष

कचरे को चाहे वो मोबाइल फोन हो से लेकर युद्धक विमान या युद्ध पोत हों, सबके कचरे को बेचकर वह भी मोटी कीमतों में बेशक कुछ टुकड़े देशी गुलाम सत्ताधीश कठपुतलियों को डालकर अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं।

पूरा यूरोप जब परमाणु बिजली घरों की भयावह परिणिति, उसकी हजारों साल नष्ट न होने वाली राख से परेशान हो बंद कर रहे हैं, जिनका जीवन काल समाप्त हो चुका है, उन परमाणु भट्टियों को बेचकर जो वास्तविकता में भयंकर रेडियो एक्टिव पदार्थ है मोटा धन कमाएगा, जबकि उसे वहां नष्ट करने में दफनाने, समुद्र में फेंकने से अकल्पनीय दुष्परिणामों के न केवल वर्तमान में वरन सहस्त्रों वर्षों तक स्थाई रूप से बने रहेंगे का अंदेशा है।

हमारे देश मेंहमारी भाग्यविधाता बनी अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता चला रही यूरोपीय एजेंट सोनिया और उसके कठपुतली प्रधानमंत्री सिंग (इस स्लेव) को मोटा अरबों डालर में मिलने वाला कमीशन सर्वोपरि है, के लिए परमाणु समझौता किया गया। इस मोटे कमीशन के लिए राष्ट्र की परमाणु भट्टियों को बंद करने के षड्यंत्र तो रचे ही गए साथ ही भारत में काम कर रहे कोयले से बिजली बना रहे न केवल प्रदेश के वरन पूरे देश के ताप विद्युत ग्रहों के कोयले में भी कटौती भी की गई, घटिया कोयला दिया गया और पूरे षड्यंत्रों के साथ बंद किए जा रहे हैं,ताकि बिजली संकट पैदा किया जा सके, जो जल विद्युत बन रही थी, है उसे भी जनता को न देकर उद्योगों को बेची जा रही है। दूसरी तरफ बांग्लादेश, नेपाल को भी बेची जा रही है, ताकि परमाणु बिजली घर लगाने के रास्ते बन सकें, अपनी कमीशन खोरी को बचाया जा सके और अमेरिका ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया में आयु पूरी कर चुकी परमाणु भट्टियों को भारत में स्थापित कर कचरे को भी मोटी कीमतें वसूल हो और दूध देने वाली गाय की तरह इन भट्टियों में लगने वाले ईंधन से भी पहले छोटी और बड़ी और बाद में मुंहमांगी कीमतें वसूली जा सके

और इस देश की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के बहाने देश की गुलामी को मजबूत किया जा सके, मात्र मोटे कमीशन के लिए।

दूसरी ओर परमाणु भट्टियों के साथ में अरबों रुपए के अन्य प्लांट, मशीनरी भी भारत को थोंप कर इस खतरनाक रेडियो एक्टिव अपशिष्टों से मुक्ति मिले, ताकि उनका देश, देश की धरती, वहां पर निवास करने वालों की सुरक्षा की जा सके। अब पाठक अंदाज लगा सकते हैं कि वह रेडियो एक्टिव सामग्री भारत में कितना कहर ढाएगी उसके बाद उसकी निकलने वाली राख जो रेडियोएक्टिव होगी और उसमें से हजारों वर्षों तक अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलेंगी ये वही किरणें हैं जिन्हें हम साधारण भाषा में एक्स-रे कहते हैं जो हमारे शरीर के पार निकल जाती है और शरीर में पाए जाने वाले फास्फोरस, कैल्सियम तक रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। जिसका परिणाम जापान में गिराए गए हीरोशिमा और नागासाकी के 65 वर्ष पुराने परमाणु बमों के परिणामों से समझा जा सकता है कि वो तत्कालीन, मानव जाति मरने के साथ ही अभी तक न केवल अपंगता से जी रहा हैं वरन आने वाली पीढ़ी भी अपंगता के साथ पैदा हो रही है। साथ ही जहां पर राख डाली जाती है हजारों वर्ष तक उसका असर रहने के कारण वनस्पति तक नहीं पैदा होती है जिसे हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था से समझ सकते हैं। जहां पर हुए हजारों वर्ष पूर्व के युद्ध के कारण अभी तक रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है और वहां घास भी पैदा नहीं होती, कहा जाता है कि वहां भी परमाणु युद्ध हुआ था। 40 दिन वहां अंधकार नहीं हुआ था, अब यदि देश में लगने वाले 20 परमाणु घरों से निकलने वालीू राख को ये संचालक, वैज्ञानिक ईंट भट्टों को बेचेंगे ही या वो चुराकर ले जाएंगे और उससे ईंटे बनाएंगे या के अपना पाप छुपाने और उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहीं न कहीं तो फेंकेंगे तो क्या होगा धरती बंजर होगी ही जो हजारों वर्षों तक वनस्पतियों को पैदा नहीं होने देगी दूसरी ओर इस राख से आसानी से परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। यदि वो राख आतंकवादियों, नक्सलाइट्स के हाथ लगेगी तो क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यही कारण है कि अमेरिका ने हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री को भेजकर परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु हथियार न बनाने की संधि पर हस्ताक्षर करवाने भेजा था। आखिर क्यों? उन्हें भी डर है कि परमाणु बिजली घरों से निकलने वाली राख से परमाणु बम न बनाए जा सके। इसके विपरीत भारत की उपजाऊ भूमि भले ही बंजर हो जाए तो और भी अच्छा यहां के गुलाम गेहूं, चावल के लिए भी यूरोप, अमेरिका पर आश्रित हो जाए और रोटी के लिए भी भीख मांगे, गेहूं, दाल, चावल की इससे बेहतर अमेरिकी और यूरोपीय आकाओं के लिए क्या हो सकता है। ये वर्तमान कांग्रेसी कमीशन खोर प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन, कृषि मंत्री शरद यादव व वर्तमान बूढ़ी फौज मर जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी इन कमीशन दुम हिलाने वाले श्वानों की नोंच खसोट को भोगेगी।

## 240 करोड़ ...

पेज 8 का शेष

### कब जागेगा आत्मस्वाभिमान? या गुलामों की औलाद रहेगी गुलाम

बेताब रहते हैं, वरन कमीशन की खातिर न केवल 120 करोड़ जनता से झूठ बोलते हैं। वरन अपने आप को भी जब जीवन के कुछ ही वर्ष भी निश्चित रूप से न बचें हो छलते हैं और कपट करते हैं, ताकि उनकी नकारा, निकम्मी औलादों को धन काम आए। इसके विपरीत जो धन वो कमीशन से इकट्ठा कर विदेशी बैंकों में जमा करते हैं। देश को और अपने आप को छलते हैं। वो अमेरिकी अपनी बैंकों का दीवाला निकाल हजम कर जाते हैं। ये हमारे सत्ताधीश चूं-चपड़ भी नहीं कर पाते और वो सब आसानी से हजम कर जाते हैं। इसके बाद भी हमारे सावन के कमीशन के अंधों इस तथ्य को नजर अंदाज करते जाते हैं। उनकी हर चाल के पैदल बन उनके हाथ मजबूत कर अपने देश पर कर्ज का बोझ लादते जाते हैं। वो अमेरिकी और यूरोपीयन हम ही से कमाते हैं। बाद में अपनी महानता और देश की गुलाम मानसिकता सिद्ध करने के लिए हम पर 10% अनुदान लुटाते हैं और हम कटोरा फैला कर भीख मांगने खड़े हो जाते हैं।

सत्यता में अमेरिका और यूरोप उस वैश्या की तरह हैं जो अपनी चालाकी से अपनी छद्म खूबसूरती के बहाने हम जैसे सम्पूर्ण पुरुष जो कि हर तरह से दाता है अपने जाल में फांहस कर धन भी कमाती है और तन,मन, निचोड़ कर अपने चालाकी, छलकपट से अपना दीवाना बनाकर भी रखती है। जब उसे लगता है ग्राहक या गरीब देश उसके चंगुल से भाग रहे हैं तो कभी स्वाइन फ्लू, कभी आतंकवाद का, एड्स का भय बेचती है तो कभी चांद पर पहुंचने की नौटंकी दिखाती है। अपने ग्राहकों को इस तरह अपने मोहपाश में बांधे रख अपनी मौज मस्ती लूटती है। उसकी ये सच्चाई जनता को न समझ आए इस लिए वो हर देश में प्यार से घुसकर या उसके अधिकारों के बलात्कार की तरह परमाणु बम हैं, रासायनिक हथियार हैं, आतंकवादी की आड़ में गुंडे भेजकर कब्जा कर लेते हैं। वहां की जनता को यौनाचार में उलझाने के लिए वहां सबसे पहले महिलाओं में वैश्यावृत्ति फैलाई जाती है सामाजिक रूप से ताकि वहां के पुरुष लड़ाके सम्मान आत्मस्वाभिमान को भूल कर हर चौराहे-चौराहे पर खड़ी वैश्याओं के जाल में उलझ कर सब भूल जाएं, जैसा कि अफगानिस्तान, ईराक, रूस में किया गया। भारत में बाल विवाह पर अंगुली उठाते हैं और बाल वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहित करते हैं। हमारी सरकार में बैठे उस श्वेतांग और संकर प्रजाति के हर छल कपट के सामने नतमस्तक उसके ताल में ताल मिलाकर न केवल नृत्य करते हैं, वरन् उसकी निगाहों में अपनी वफादारी की श्रेष्ठता सिद्ध करने का कोई मौका नहीं चूकती चाहे वो घरेलू हो, महाद्वीपीय या अंदर महाद्वीपीय वैश्विक मुद्दा और उसकी चाल हो। हमारे सत्ताधीशों का यो लालच, स्वार्थी और भ्रष्ट प्रवृत्ति ने अमेरिकी और यूरोपीय राष्ट्रों को न केवल गुलाम, ऋणी और भिखारी बना दिया। 120 करोड़ लोगों के 240 करोड़ हाथों को जो विश्व अभी भी फैला दें तो न केवल मुट्ठी में कर विश्व के पुनः सरताज बनने में सक्षम हैं। साथ ही पुनः विश्व के प्रकाश स्तंभ बन कर पुनः नए शांतिपूर्ण विश्व की रचना कर सकते हैं।

इसके विपरीत सच यह भी है कि राष्ट्र को अंग्रेजों की प्रत्यक्ष गुलामी से मुक्त हुए 62 वर्ष गुजर चुके पर जिस देश की 90% जनता को सड़कों पर चलने का तमीज न हो तो वो कैसे जिंदगी को अपनी और देश की जनता की जिंदगी को प्रकाशित कर समृद्धि दे पाएगा। कल तक सड़कें अच्छी न होने से लहरा कर चलते हैं वो अब यदि सड़कें अच्छी मिलने लगी तो अब किनारों पर चलने में शर्म आती है। इसलिए अब इठलाकर लहरा कर चलते हैं। हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते, इसके चक्कर में हर दिन 5000 लोग दुर्घटनाओं के शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। इसके विपरीत हम सुधरना नहीं चाहते है, जब हम सड़कों पर ढंग से नहीं चलते तो जिन्हें हमने चुन कर सत्ता सौंपी है उनके कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सत्ता की सड़कों पर तरीके से चलेंगे। परिणाम हमारे सामने हैं। वो भी अपनी कमीशन खोरी के लिए जनता को समृद्धि के नाम पर कर्ज लेकर, भीख मांगकर घी पीकर लहरा कर चल रहे हैं।

**कब जागेंगे? या देश की धरती महसूस करेगी-** न तू हिन्दु रहेगा, न मुसलमान रहेगा, गुलाम की औलाद है तू गुलाम रहेगा।

**राष्ट्रगीत में गाएगा-** जन, गण, मन, अधिनायक (जिनके हम अधीन थे जो हमारे नायक थे, पूर्व में अंग्रेज और अब अमेरिकी) जय है भारत के भाग्य विधाता।

### भ्रष्टों और कमीशन खोरों ने महान भारत को भिखारी बना दिया

# 240 करोड़ कर, कर सकते दुनिया मुट्ठी में

विश्व को धर्म, आध्यात्म, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, भवन स्थापत्य जैसे गूढ ज्ञान बांटने वाला 84 करोड़ देवी देवताओं वाला या ऐतिहासिक सहस्त्रों वर्षों की गुलामी भोगने वाला स्वार्थी, निकम्मों का ये राष्ट्र कब तक अमेरिका, यूरोपीय अनुदानों, ऋणों से यूरोपीय म्लेच्छों के समय बाधित प्रचलन से बाहर के कचरे को ढोता जीता रहेगा। इसके बाद भी हमारे स्वार्थी मक्कार भ्रष्ट कमीशन खोर सत्ताधीशों जिनके पास स्वयं का आत्मसम्मान तो दूर देश के आत्मसम्मान को बचाए रखने की भी इच्छा नहीं है कल तक वो श्वेतांगों के संरक्षण में जी रहे थे। अब वो विश्व भर के सारे संकर प्रजाति के इशारे पर नाच कर पूरे देश को गिरवी कर चुकी हैं। हमारे देश के भ्रष्ट सत्ताधीश, भ्रष्टाचार और कमीशन के चलते अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हवाले कर जनता का घोर शोषण करवाने के कार्यों में पूर्णतया समर्पित है। हमारे देश का पानी और उससे बनाई गई बिजली पर भी हक विदेशियों का होगा और वो मनचाही कीमत पर पानी और बिजली हमारे राष्ट्रवासियों को बेचेंगे।

हमारे स्वार्थों और हमारे हितों में आत्मसम्मान का अभाव ही हमारे सहस्त्रों वर्षों की गुलामी का मूल कारण रही है। चाहे वो सेल्युकस या अलेक्जेंडर जैसे लोगों ने यूरोप से निकलकर हमारे देश में घुस कर कब्जा कर लेते हैं, बाद में हुण, शक, मुस्लिम उसके बाद पुर्तगाली उसके बाद अंग्रेजों जैसी कौम भी 300, 400 वर्ष राज्य करके आसानी से चली जाते हैं, उनके चले जाने के बाद भी हम आजादी के 60वर्षों बाद भी अपने राष्ट्रगीत में उनके जयकारे लगाते और उनको भाग्य विधाता बताते और बनाते हैं।

धन्य है इस राष्ट्र के भ्रष्टों, कमीशन खोर, महास्वार्थी और मक्कार सत्ताधीशों को जो अपना विदेशियों को सौंपते हैं। उनकी न केवल समय बाधिक कचरों में उनकी तकनीकी, जिसमें मोबाइलों, दूरभाषों से लेकर लड़ाकू जहाज उनके यहां कचरे में पड़े हजारों टन के विमान वाहक पोतों, उनके हजारो वर्षों तक नष्ट न होने वाले रेडियोधर्मी कचरे तक को खरीदने के लिए मात्र मोटे कमीशन के लिए न केवल **शेष पेज 7 पर**

### शादी पवित्र बंधन नहीं, अब नापतौल का खेल

# शादी नहीं सौदेबाजी, अग्रिम चाहिए गारंटी-वारंटी

### नारियों का गिरता अनुपात बढ़ती महत्वाकांक्षाएं,बढ़ती उम्र, बढ़ते तलाक, गिरता सामंजस्य

पूरा राष्ट्र विभिन्न भाषा-भाषी धर्मों, प्रांतों में बंटा हुआ है, हरकिसी के अपने रीति-रिवाजों, खानपान, रहन-सहन में भी विभिन्नता होती ही है। इसके विपरीत प्रकृति के चक्र को निरंतर घूमते रहने के लिए मानवों में शादी की महत्वपूर्ण परंपरा हर समाज में सामाजिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। हिन्दुस्तान में कल तक इस शादी के बंधन को स्त्री-पुरुष के तन-मन के बंधन से ऊपर दो आत्माओं के, दो परिवारों के मिलन जिसे भगवान के घर तय हुआ रिश्ता माना जाता था, अब वह सामाजिक बंधन, तन,मन, और आत्मा के मिलन का नहीं वरन नापतौल का हिस्सा बन चुका है। अब लड़की जहां मां-बाप या संरक्षकों न बांध दिया है, जिंदगी भर निभाना और गुजारने की बात गांवों की अनपढ़ और मीडिल पास पीढ़ी तक सीमित रह गए है। वह भी निम्न और निम्न मध्यमवर्गीय समाजों में । पूरे उत्तरी और मध्य भारत में हर समाज में एक तरफ तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात तेजी से गिरा है, यह घोर गंबीर हालात वैश्य समा, जिसमें जैन, अग्रवाल, माहेश्वरी आते हैं यहप्रतिशत 50 से 60% ही स्त्रियां रह गई हैं। उच्च शिक्षित होने केकारण 10% लड़कियां पढ़ाई करते समय या नौकरी मेंर हते दूसरे समाजों में शादियां कर लेती हैं। दूसरी और 10% लड़कियां उच्च शिक्षा और कैरियर बनाने के चक्कर में 30-35 वर्ष तक शादियां नहीं करती या उनकी महत्वाकांक्षाओं के चलते उनकी तराजू में कोई फीट नहीं बैठता। 10% लड़कियां जो ऊंची नौकरियां करने लगती हैं और मोटे वेतन के साथ घर लौटती हैं भले ही वो घर से निकलकर कुछ भी कर रही हों उनके मां-बाप, भाई-बहन दुध देती गाय को कैसे दोहना छोड़, उसकी शादी में क्यों और कैसे पैसा खर्च करें के कारण हर रिश्ते में 1760 नुक्श निकालकर लड़की का दिमाग सड़ा कर शादी नहीं होने देते। अगर येनकेन प्रकारेण शादी हो भी गई तो घर तुड़वाने में मां-बाप, भाई-बहन अपनी भूमिका निभाकर ऐसी गायों को वापस घर लाकर बांध देते हैं। लड़की बिचके नहीं 10-10 वर्ष तक ऐसी नौटंकीयां करते रहते हैं। अखबारों में विज्ञापन देगें। मैरेज ब्यूरो में पंजीनय करवा देंगे। शादी की इंटरनेट साइटों पर डाल देंगे, डाटा और लड़की का मोलतोल करते रहेंगे। इस चक्कर में अनेकों लड़कियों की उम्र 40 हो जाना अब आम बातहो गया है। स्वाभाविक है जब लड़कियों की उम्र 30 से ऊपर निकलने लगती है वो अपने पास दूर-दूर के रिश्तेदारों से लेकर नौकरों ड्रायवरों, अपने मित्रों इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को शारीरिक भूख मिटाने के लिए उपयोग करने की आदी हो जाती है और परिणाम ताजे उदाहरण में अमृता पांचोली हत्याकांड जो इंदौर के भारतीय प्रबंध संस्थान की प्राध्यापक थी जनता के सामने है। वैसे इस मामले में पुलिस ने अपनी आदत और चरित्र के अनुसार गजब की लीपापोती की और बेकसुर ड्रायवर को आरोपी बना कर असली आरोपी से लेनदेन कर बचा दिया गया। ये हालात चारों तरफ हैं, बस जो चल रहा है चलने दो हमें क्या करना है। इसके विपरीत इस राष्ट्र का इन सबके चलते न केवल सामाजिक ढांचा बिगड़ रहा है। वरन यौन अपराधों तालाबों में भी गुणात्मक वृद्धि हो रही है। हर समाज के ठेकेदार इसमें भी अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगेरहते हैं। उन्हें तो उसमें भी अपने न केवल लाभ वरन यौनाचार के लिए भी सरपट खुले रास्ते नजर आते हैं। ये सब भी अब संभ्रांत समाजों से लेकर निम्नवर्गों में भी पाया जाने लगा है। वैसे भी अधिकांश परिचय सम्मेलनों में जाकर इन सब तथ्यों की सत्यता स्पष्ट देखी जा सकती है। वैसे परिचय सम्मेलनों में विवाह संबंधों में ज्यादा नापतौल और भाव-ताव होते हैं। सही मायने में परिचय सम्मेलन बेशक बेहद उपयोगी है पर इसके विपरीत सच्चे अर्थों में स्त्रियों के घटते अनुपात और शिक्षा के कारण स्त्रीयों के लिए पुरुषों की बड़ी मंडी बन चुके हैं, जहां अब स्त्रीयां अपनी इच्छानुसार पुरुषों से खुलकर न केवल सौदेबाजी वरन् शर्तों, गारंटी, वारंटी तक तय करने से नहीं चूक रही है। अब उन्हें पति नहीं घर के बाहर बंधे पालतू श्वान **शेष पेज 2 पर**

### जो है नाम वाला, वही तो बदनाम है

# समयमाया को बदनाम करने का अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र

### गूगल पर समयमाया को खोजने पर देखे जा सकते हैं हथकंडे बदनाम करने के

समयमाया ने अपने पहले प्रकाशन जन. 1998 से लेकर वर्तमान तक राष्ट्र और विश्व की जनता के आंसुओं को पोंछने के लिए एकल युद्ध कर रहे हैं। अपने पहले प्रकाशन मेंही अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतियों और एशिया महाद्वीप में उसके द्वारा पाले पोसे जा रहे आतंक के विरुद्ध सीधी कलम चलाई तो राष्ट्र में सबसे पहले न्यायालयीन व्यवस्था में डग-डग फैले भ्रष्टाचार के विरुद्ध सीधे कुठाराघात कर न्यायालयों को न्याय का मंदिर बनाने का प्रयासहमारी सीधी बात और लगातार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे जा रह ई-मेल का ही परिणाम था कि भारतीय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने 25/1/2001 को अपने राष्ट्रीय उद्बोधन में यह स्वीकार किया कि भारतीय न्यायालय, न्याय के मंदिर नहीं वरन् जुए के अड्डे हैं जो जितना बड़ा दांव खेलेगा उसे उतना न्याय मिलेगा। यह कहकर श्री अजमेरा की सत्यता एकल युद्ध में अप्रत्यक्ष हौंसला बढ़ाया। इसके विपरीत जब सन 1998 में सीधा न्यायालयीन व्यवस्था के भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रकाशित कर आवाज उठाई तब जबलपुर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को न केवल भयानक नागवार गुजरा वरन् वह राष्ट्र का पहला जहरीले सच का प्रकाश था। इसलिए सदा के लिए कुचल देने और भविष्य में पत्रकारों को सबक सिखाने के लिए लामबंद होकर सबसे पहले म.प्र. की अधिवक्ता परिषद् को श्री अजमेरा के खिलाफ आंदोलन के

लिए भी उकसाया गया। जैसे ही यह बात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता स्व. हीरासिंग चौहान को मालूम पड़ी तो उन्होंने आंदोलन बंद करवा कर श्री अजमेरा को बुलवा कर खूब डांटा और यह जानने की कोशिश की कि क्या श्री अजमेरा दबाव बनाने के लिए लिख रहे हैं, जबकि इन सब 4-5 दिनों में पूरे जबलपुर के वरिष्ठ पत्रकार तक श्री अजमेरा को मरवा डालने के षड्यंत्र के बारे में जान गए थे।यह बात सभी अधिकारियों और पुलिस को भी लग चुकी थी कि किसी भी वक्त कोई भी गुंडा श्री अजमेरा को निंपटाने की तैयारी में है। श्री अजमेरा के शुभचिंतक, पत्रकार तक उनकी जान की सलामती की दुआएं मांग रहे थे।

जैसे ही स्व. हीरासिंह चौहान के बुलवांने की खबर सब जगह फैली, क्योंकि म.प्र. बार कौंसिल के अधीक्षक के पद पर बैठे पत्रकार रमाकांत वाजपेयी भी हर इस बात पर नजर रखे हुए थे कि श्री अजमेरा के विरुद्ध कहां क्या चल रहा है और उसकी खबर सीधे सभी वरिष्ठ पत्रकारों को मिल जाती थी। जब स्व. हीरासिंग चौहान ने बुला कर डांटा तो उन्होंने अंत में पूछ ही लिया कि क्या सच लिखकर मैंने भारी अपराध कर दिया है। आपने बहुत डांटा है तो स्व. चौहान ने ठंडे होकर बोले बेटे मैं तो ये देख रहा था कि केवल तू लिखना ही जानता है या टकराना भी, तूने जो लिखा है रो सब सच है। परंतु तेरे साथ कुछ हो उसके पहले मैं यह जानना चाहता था कि ये लिखने के पीछे उद्देश्य क्या था और सच ही जनता की लड़ाई है। तो तूने बहुत अच्छा किया है। बाद में उन्होंने ही सब को शांत कर दिया। उसका ही परिणाम है कि वर्तमान में उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने अपनी सम्पत्तियों को सार्वजनिक स्वीकार किया, अन्यथा समयमाया समाचार पत्र के पहले पूरे देश के बड़े से बड़े समाचार पत्र की हिम्मत नहीं थी कि न्यायालय के न्यायाधीशों की आलोचना कर सकें।

तब से लेकर अभी तक समायमाया ने देश और दुनिया की जनता की बेखौफ होकर सीधी लड़ाई लड़ी है। चाहे वह अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बुश या अब ओबामा हो सीधे ही उनकी बत्तमीजीयों का सीधा आईना दिखाते हुए अपनी साइटों को अपडेट करते हुए व्हाटि हाऊस के भोजे हैं, जिसमें अफगानिस्तान, ईराक पर आक्रमण के विरुद्ध रोकने की गुहार या आतंक को पालकर, हथियार बेचने के विरुद्ध ललकार, एड्स, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू के षड्यंत्रों के विरुद्ध जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन के फटकार सुनामी के हथकंडों की आड़ में फोड़े गए बमों की दहाड़ या भारत के म.प्र. प्रांत के खंडवा जिले के खालवा ब्लाक में भूखे बच्चों की पुकार, सबको बेबाकी और प्रशासन के विरुद्ध समयमाया लगातार आवाज उठाता रहा है, उठाता रहेगा, समयमाया के प्रधान सम्पादक का ये प्रण है, जब तक इस धरती की यात्रा में शरीर में सांस, मस्तिष्क जागृत है हर असहाय की सहायता और जंग चलती रहेगी।

स्वाभाविक था विश्व के सत्ताधीशों जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन से लेकर भारत की केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की सच्चाई से पिछले दस वर्षों में राष्ट्र और विश्व की जनता के हित मीडिया जगत की लीक से हटकर हजारों प्रकाशन जनजागृति के लिए समयमाया ने लगातार कर अपना स्वर्णिम इतिहास लिखा है जिसे पाठक जानते हैं **शेष पेज 5 पर**

## प्रतिबंधात्मक सूचना

**इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.**

**आज्ञा से**

**प्रधान संपादक**

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित.

कम्प्यूटराईजेशन- सुनील जोशी 93290-40982, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2530859 मो. 93007-55803